

अपने फायदे के लिए विभिन्न देशों में तख्ता पलट का पुराना इतिहास रहा है अमेरिका का

ईरान में अमेरिका ने तख्ता पलट की दूसरी बार कार्यवाही की है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 मार्च। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने अमेरिकी शक्ति के बारे में एक असहज सवाल फिर से उठा दिया है: क्या बाहर से थोपे गए शासन परिवर्तन कभी स्थायी स्थिरता पैदा कर पाते हैं? एक सदी से भी अधिक समय से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन सरकारों को गिराने के लिए बार-बार सैन्य बल या गुप्त अभियानों का इस्तेमाल किया है, जो उसे शत्रुतापूर्ण या असुविधाजनक लगती हैं। इसके परिणाम एक चेतावनी देने वाली कहानी बताते हैं, हालांकि कुछ हस्तक्षेपों ने अस्थायी व्यवस्था बनाई, लेकिन कई ने अस्थिरता, संघर्ष और भू-राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जो उन शासनकालों से कहीं अधिक समय तक चली, जिन्हें हटाया गया था।

सबसे प्रारंभिक उदाहरण 1893 का है, जब हवाई में अमेरिकी व्यापार हितों ने अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य समर्थन के साथ क्वीन लिली योकलानी

- पहली बार 1953 में हस्तक्षेप किया था, जब ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया था। तब अमेरिका ने मोसादेघ का तख्ता पलट कर शाह रजा पहलावी के नेतृत्व में राजतंत्र स्थापित किया। जनता के अमेरिकी विरोध, शाह की तानाशाही के कारण 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया।
- इस्लामिक गणराज्य ईरान हमेशा से अमेरिका विरोधी था। लम्बे समय तक धमकी देने के बाद अन्ततोगत्वा अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया।
- इस तरह के हस्तक्षेप की शुरुआत अमेरिका ने 1893 में हवाई में की और वहां की क्वीन लिली को सत्ता से अपदस्थ कर अपनी मनपसंद सरकार बनाई तथा 1959 में हवाई को अमेरिका का 50 वां राज्य घोषित कर दिया।
- इसी प्रकार अमेरिका ने कई देशों, ग्वाटेमाला, क्यूबा, चिली, डोमिनियन रिपब्लिक, ग्रेनेडा, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में सैन्य कार्यवाही कर तख्ता पलट करवाए। कहीं तो ये तख्ता पलट जनता को और उस देश को रास आए पर अधिकांश देशों में जनता की मुश्किलें ही बढ़ीं।

की सरकार को उखाड़ फेंका। राजतंत्र को एक अस्थायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने अंततः 1898 में हवाई को संयुक्त राज्य

अमेरिका में मिला लिया। लंबे समय में, यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया और 1959 में इसे 50वां अमेरिकी राज्य स्वीकार कर लिया गया, हालांकि

इसकी सरकार उखाड़े जाने को ऐतिहासिक रूप से विवादित माना जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पदीय कर्तव्य में कार्यवाही की हो, तो बिन मंजूरी मुकदमा नहीं करें

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों के तहत कोई कार्यवाही की हो तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में

- हाईकोर्ट ने जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी राजीव दत्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश रद्द किया।

याचिकाकर्ता की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी राजीव दत्ता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता विजय शर्मा ने मार्च, 2002 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि सुबह लगभग पांच दर्जन लोग उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या अमेरिका के हथियार भंडार खाली होने लगे हैं?

वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमले के पहले दो दिन में ही अमेरिका 5.6 बिलियन डॉलर के हथियार ईरान पर सैन्य कार्यवाही में खर्च कर चुका था

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 मार्च। क्या ईरान युद्ध तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका के हथियारों के भंडार खत्म कर रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में सैन्य अभियान शुरू होने के मात्र पहले 48 घंटों में ही अमेरिका लगभग 5.6 अरब डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। यह अनुमान उस रिपोर्ट पर आधारित है, जो अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की गई थी। ये अनुमान अमेरिकी सरकार के इस दावे से काफी अलग है कि ईरान मिशन से अमेरिका की "सैन्य तैयारियों में तेजी से कमी नहीं आ रही है।"

हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान में 5000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है और 50 से अधिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा ईरान की सरकार के मुख्यालय, खुफिया ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कई तरह की सैन्य साधनों का इस्तेमाल किया है, जिनमें बी-1 बमवर्षक, बी-2 स्टेलथ बमवर्षक और बी-52

- वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा अमेरिका की कांग्रेस में प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट सरकार के दावों से मेल नहीं खाती। ट्रंप सरकार का दावा है कि ईरान मिशन से अमेरिका के हथियारों का जखीरा कम नहीं होगा।
- हाल ही में अमेरिका ने ईरान में 5000 लक्ष्यों पर बमबारी की, 50 जहाज नष्ट किए। ईरान के कई सरकारी कार्यालय व प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए। इसमें अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक सैन्य उपकरण व हथियार तैनात इस्तेमाल किए हैं।
- संभावना है कि वाइट हाउस इस सप्ताह पूरक रक्षा बजट की मांग कर सकता है जो काफी बड़ा होगा।
- इसी के साथ यह संभावना भी है कि अमेरिका व इजरायल अब लैज़र निर्देशित बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बमवर्षक शामिल हैं। इसके अलावा, लूकस ड्रोन, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम और थाइ एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसे सिस्टम भी इस्तेमाल किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान में शामिल लड़ाकू विमानों में एफ-15, एफ-16, एफ-18, एफ-22 और

एफ-35 स्टेलथ फाइटर शामिल हैं। इनके साथ ए-10 अटैक जेट और ईए-18जी इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान भी तैनात किए गए हैं। ई-2डी एडवॉन्स हॉकआई विमान और हवाई संचार रिले प्लेटफॉर्म भी तैनात किए गए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने स्पीकर बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया

स्पीकर बिड़ला पर खुला पक्षपात करने का आरोप तो है ही साथ ही उन पर कांग्रेस सदस्यों को लेकर झूठे दावे करने का भी आरोप लगाया गया है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 10 मार्च। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण मंगलवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष-समर्थित एक प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, जिसमें अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग की गई है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भी सदन की कार्यवाही में प्रमुख मुद्दा बनने की संभावना है। विपक्ष ईरान के मुद्दे पर भारत की स्थिति, और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा दी गई छूट सहित, कई विषयों पर सरकार की आलोचना कर सकता है।

एक ओर मुद्दा, जो सदन में उठ सकता है, वह है चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। खबरों के

- बजट सत्र के दूसरे भाग के एजेंडा में हालांकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ही एक मात्र कार्यक्रम है, लेकिन ईरान युद्ध और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, बंगाल में एसआईआर जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए जाएंगे।

अनुसार, इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इस मामले को लेकर संसद में तीखी बहस होने की संभावना है।

कई विपक्षी नेताओं ने ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उनका आरोप है कि अध्यक्ष ने सदन में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ गलत दावे किए, जब उन्होंने लोकसभा में कुछ

अप्रत्याशित घटनाओं का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित न हों।

नोटिस दिए जाने के बाद, ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि इस मामले पर फैसला होने के बाद ही वे सदन में आएंगे।

अविश्वास प्रस्ताव के अलावा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र राज्यपाल की शपथ ली

मुंबई, 10 मार्च। महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने लोकभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और

- वे महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल हैं।

गोपनीयता की शपथ दिलाई।

लोकभवन में शपथ ग्रहण के बाद, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। वे महाराष्ट्र के 22 वें राज्यपाल बने हैं। लोकभवन में शपथ विधि कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से हुई तथा समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 10 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुझाव दिया कि संपत्ति के अधिकारों में मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालत जल्दबाजी कर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहती। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि शरीयत के प्रावधानों को हटाने से मुस्लिम महिलाओं को 1925 के भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत अधिकार मिल सकेंगे।

हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और इस पर अंतिम निर्णय संसद और सरकार को ही लेना होगा। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं देते।

इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा

'मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हक मिले'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका एक ही तरीका है यूनियफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी)

- सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए कही। मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर इस रिट याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उन प्रावधानों को चुनौती दी गई, जो महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति का हक नहीं देते हैं।
- चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने माना कि शरीयत को हटा दिया तो कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार का कोई अन्य कानून नहीं है।
- कोर्ट ने कहा, इस समस्या का समाधान यूनियफॉर्म सिविल कोड से ही हो सकता है। पर इसका क्रियान्वयन संसद का विशेषाधिकार है।

न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति बागची ने एक पुराने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। याचिकाकर्ता

कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, जो चाहती हैं कि कानून में उन्हें वैतुक संपत्ति में हिस्सा मिले।

पीठ का मानना था कि अगर शरीयत को हटा दिया जाता है, तो

कानूनी खालीपन पैदा हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार के लिए कोई दूसरा कानून मौजूद नहीं है।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि उत्तराधिकार का कानून एक नागरिक अधिकार है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता। उन्होंने तीन तलाक मामले में अदालत के उस फैसले का उदाहरण दिया, जिसमें इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब पीठ ने पूछा कि शरीयत के तहत उत्तराधिकार के प्रावधान को खत्म करने के बाद वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था क्या हो सकती है, तो प्रशांत भूषण ने याचिका में संशोधन करने पर सहमति जताई। इसके बाद अदालत ने आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।

राज्यपाल बागडे आईसीयू में भर्ती

जयपुर, 10 मार्च। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को आज एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया है। राज्यपाल आज अपनी रूटीन जांच करवाने दोपहर करीब 1 बजे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको भर्ती कर लिया। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक, राज्यपाल ब्लड समेत

- रूटीन जांच के लिए एसएमएस अस्पताल गये। वहां घबराहट के बाद बुखार आ गया, जिसके बाद उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया।

अन्य रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। यहां जांच के दौरान घबराहट होने के बाद उनको बुखार आ गया, जिसके बाद उनको मेडिकल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंद हो सकते हैं कई होटलों और रैस्त्रां के किचन

अगर एलपीजी गैस की आपूर्ति जल्दी ही व्यवस्थित नहीं हुई तो

- ईरान संकट ने देश के पेट्रोलियम व एलपीजी सैंक्टर में भारी कमी पैदा कर दी है, जिससे सबसे भारी संकट हॉस्पिटैलिटी सैंक्टर के समक्ष उत्पन्न हो गया है।
- भारी मंदी से उबर कर धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा होटल उद्योग एक बार फिर मंदी की ओर अग्रसर हो सकता है। इस उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि हालात बिगड़े इससे पहले हस्तक्षेप करे। सरकार हॉस्पिटैलिटी सैंक्टर के लिए कॉमर्शियल एलपीजी की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित करे तभी इस उद्योग को बचाया जा सकता है।
- हॉस्पिटैलिटी सैंक्टर ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रखा है, अगर यह सैंक्टर प्रभावित हुआ तो बेरोजगारी में भी भारी वृद्धि हो सकती है। साथ ही देश की जीडीपी भी प्रभावित हो सकती है।

कुछ ही दिनों में बड़े पैमाने पर रेस्तरां बंद होने की नौबत आ सकती है। इस कमी का तत्काल कारण भारत की सीमाओं से काफी दूर दिखाई देता

है। पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब ग्लोबल एनर्जी स्पलाई चैन को प्रभावित करने लगा है, जिसमें खाड़ी देशों से आने वाली एलपीजी की आपूर्ति भी

शामिल है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, और इसका अधिकतर हिस्सा होमजु स्ट्रेट से होकर आता है। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट या सिक्यूरिटी रिस्क बढ़ने से टैंकरों की आवाजाही धीमी हो सकती है, माल ढुलाई और बीमा लागत बढ़ सकती है और भारत जैसे आयात करने वाले देशों में एलपीजी की उपलब्धता कम हो सकती है।

स्पलाई में रुकावट की संभावना को देखते हुए अधिकारियों ने कथित तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य घरों में गैस की कमी को रोकना है, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम यह हुआ है कि रेस्तरां, होटल और केटरिंग इकाइयों जैसे व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ गया है। चूंकि रेस्तरां बड़े व्यावसायिक सिलेंडरों पर ही निर्भर रहते हैं और रोज बड़ी संख्या में उनका

उपयोग करते हैं, इसलिए स्पलाई में थोड़ी सी भी रुकावट से काम रुक सकता है।

इसका असर केवल रेस्तरां मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा। आतिथ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, रसोइये, वेटर, डिलीवरी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और सप्लायर, जिनमें से कई लोग रोज़ की मजदूरी या कम मासिक आय पर निर्भर होते हैं। यदि बड़ी संख्या में रेस्तरां बंद होते हैं, चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हों, तो इससे शहरों में हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इस संकट का एक व्यापक आर्थिक पहलू भी है। हॉस्पिटैलिटी इण्डस्ट्री अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान लगे गंभीर झटके से उबर पायी है। कई प्रतिष्ठान अब भी उस समय लिए गए कर्ज चुका रहे हैं और साथ ही बढ़ते किराए, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों और बढ़ते श्रम खर्च का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जयपुर, 10 मार्च। विधानसभा का बजट सत्र 24 दिन तक चलने के बाद, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

सत्र के अंतिम दिन नगरपालिका संशोधन बिल पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे बजट सत्र की

- स्पीकर देवनानी ने कहा कि बजट सत्र में कुल 24 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली।

समीक्षा प्रस्तुत की। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि बजट सत्र के दौरान कुल 24 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही संचालित हुई, जिसमें विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के साथ-साथ जनहित के मुद्दों पर भी बहस हुई। सत्र की समाप्ति पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

विचार बिन्दु

जिसमें दया नहीं उसमें कोई सदगुण नहीं। -हरजित मोहम्मद

राजनीति में सार्वजनिक और निजी नैतिकता के सवाल

देश में राजनेताओं और प्रशासन तंत्र के अधिकारियों में नैतिक गिरावट आज के समय की सबसे गंभीर चिंता बन चुकी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नेता और प्रशासक कितने ईमानदार, जिम्मेदार और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले हैं। जब राजनीति और प्रशासन में नैतिकता कमजोर होने लगती है, तब उसका सीधा असर समाज, शासन और जनता के विश्वास पर पड़ता है, जिसे हम आज स्पष्ट देख रहे हैं। इससे जनता भी अनैतिकता के बहाव में बहने लगती है। राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानना अब इतिहास के पन्नों में चला गया है। वह जमाना दंतकथा जैसा लगने लगा है जब नेता और प्रशासनिक अधिकारी देश और समाज के हित के लिए अपने निजी स्वार्थों का त्याग कर देते थे। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दौर में कई ऐसे नेता और प्रशासनिक अधिकारी हुए जिन्होंने नैतिकता, ईमानदारी और त्याग को अपने काम का मूल आधार माना। लेकिन समय के साथ-साथ राजनीति और प्रशासनिक तंत्र का स्वरूप बदलता चला गया और इसमें सत्ता, धन और व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इस पर अलग-अलग राय हो सकती है कि राजनेताओं ने प्रशासन को भ्रष्ट किया या प्रशासनिक अहलकारों ने राजनेताओं को खराब किया। अब तो राजनीति में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य जनसेवा नहीं बल्कि सत्ता प्राप्त करना और उससे मिलने वाले लाभ उठाना बन गया है। चुनावों में भारी मात्रा में धन खर्च इमीलिए किया जाता है, जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने के उद्यम होते हैं। इस प्रकार की राजनीति में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन खर्च करके सत्ता में आता है, तो वह सत्ता में आने के बाद उस धन को वापस पाने या अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेगा ही। प्रशासनिक तंत्र में भी नैतिकता की गिरावट सबको दिख रही है। प्रशासन का मुख्य काम कानून की पालना करवाना और समस्त जनता को समान रूप से निष्पक्ष सेवाएं देना होता है। लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर या व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकारियों का कर्तव्यों से समझौता करना आम हो चला है। नैतिकता में आई गिरावट के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख है राजनीति का व्यवसायीकरण। नए डिजिटल प्रचार के युग में बाजार की चुसपैठ जीवन के हर क्षेत्र में हो गई है। राजनीति अब सेवा नहीं रह गई है, बल्कि लोगों के लिए करियर और कमाई का साधन बन गई है। दूसरा कारण है चुनावी व्यवस्था में धन, बाहुबल और कट्टर वैचारिकी का बढ़ता प्रभाव। तीसरा कारण है वृहद समाज में नैतिक मूल्यों का कमजोर होना और सत्ता प्राप्त करने की अंधी दौड़। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र की कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार योग्य और ईमानदार लोगों को अवसर नहीं मिल पाता, जबकि प्रभावशाली या धनवान प्रथमिकता पा जाते हैं। इससे राजनीति में अच्छे और नैतिक लोगों की भागीदारी कम होती चली गई है। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता की गिरावट का सबसे बड़ा नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। और जब भ्रष्टाचार बढ़ता है और समाज में असमानता और असंतोष बढ़ने लगता है और लोगों का अपने नेताओं और अधिकारियों पर भरोसा टूटता है, तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है।

सार्वजनिक नैतिकता, या कहें कि नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के नैतिक स्तर में गिरावट काफी हद तक सरकारी काम के बड़े पैमाने पर फैलाव और सत्ता के केन्द्रीकरण की वजह से भी है। इस व्यवस्था में हर स्तर के फैसले मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारियों की मर्जी से होते हैं। इससे सरकार में बैठे लोगों को अपनी ताकत के इस्तेमाल में मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। ऐसी व्यवस्था ने राजनेताओं व प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोगों का तो मूल्य बढ़ा दिया है, मगर निजी और सार्वजनिक नैतिकताओं के मानदंडों को संकुचित कर दिया है। ऐसे माहौल में राजनेताओं के लिये नारे लगाना और बड़े दावे करना सामान्य हो गया है। कोई नेता हर साल लाखों नई नौकरियों का वादा कर देता है, हालाँकि उसे पता है उसके पास उस संख्या के एक-चौथाई लोगों को भी काम देने का कोई तरीका नहीं है। नेताओं ने यह भी जान लिया है कि वे जो वादे वे चुनावों में जनता से करते हैं जनता उनसे उनका कभी हिसाब नहीं मांगेगी। जनता के हाथ में वोट के अलावा कोई ताकत नहीं है। चुनावों में भी उनको पसंद बहुत सीमित होती है। थोरे फैसले राजनैतिक दल करते हैं। बुद्धिजीवी भी इस बात पर रोशनी डालने में नकासत हैं कि आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ऐसी क्यों होती चली गई है? प्रशासन के राजनीतिकरण के तर्क को समझने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है। उदारवादी मूल्यों के लिए समर्पित पुराने नेता आजादी की लड़ाई की देन थे, जबकि उनके बाद आने वाले लोग सत्ता की लड़ाई में लगे हुए रहे, जो आज चरम पर हैं। वे सभी जो मजलूमों के हितों की मुखर आवाज़ उठाने के लिये मुजाएँ उठाते थे वे भी सत्ता के लालच में बिगड़ते चले गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होने के बजाय आजादी के पहले की परंपरागत सामंती छाया में सुकून पाती रही। सवाल उठाना जा सकता है कि राजनेता जैसे हैं, वैसे क्यों हैं? यह जानने के लिए कभी गंभीरता से बुद्धिजीवियों ने विचार ही नहीं किया। इस पर भी नहीं कि राजनीतिक प्रक्रिया गंदे लोगों को कैसे या क्यों ऊपर उठा लाती है। समाज की भूमिका और उसके सामान्य सरोकारों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होती। समाज और उसे चलाने वाले धर्म के नेता भी वर्तमान में बिगड़ल राजनेताओं की होड़ करने में लगे नज़र आते हैं। मगर सभी बुराइयों का दोष राजनेताओं पर डाल देना इस मुद्दे से बचना है। होशियार छात्र या प्रोफेसर जो घर पर कम सैलरी वाली नौकरी के बजाय विदेश में आरामदायक नौकरी पसंद करते हैं, भरपूर प्रैक्टिस करने वाले वकील और डॉक्टर अक्सर अपनी आय छिपाने में नहीं हिचकित करते, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो पागलों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पाने की कोशिश करते हैं, व्यापारी जो जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है और सही कनेक्शन वाला आदमी सब सेवाएँ पा जाता है मगर कमजोर व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं के लिए लाइन में लगा रह जाता है। यह भी कैसी नैतिकता है। समाज के सभी हिस्सियदार लोग क्या विधानमंडलों में बैठे अपने प्रतिनिधियों जितने ही नैतिक रूप से कमजोर नहीं हैं? सच तो यह है कि राजनेता उसी भ्रष्ट सामाजिक माहौल में बढ़ते हैं जिसमें दूसरे समूह फलते-फूलते हैं। बस सबको चाहें अलग-अलग होती है। लोकतांत्रिक राजनीति की अपनो ज़रूरत होती है, जिसे सबसे जरूरी है, प्रचलित रूढ़ानों को फाँलो करना, मौजूदा बकवास को दोहराना, लोकप्रियता और पब्लिसिटी के लालच में पड़ना है। यह बुलंद किया जाता है कि नारे लगाने वाली आवाज़ें कितनी भी ज़्यादा और जोरदार क्यों न हों बकवास बकवास ही रहती है। इसलिए, अगर आजकल के मीडिया बकवास से परे हों, अगर राजनेता आखिरी मिन्ट में राजनीतिक वफादारी बदल लेते हों और अगर नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के फायदे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताते जाते हों, तब आन आदमी निराश होकर अपने हाथ खड़े न करे तो क्या करे। वर्तमान में बदले की भावना वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति है। किसी राजनेता से इससे बचने की उम्मीद किसी को नहीं रही है। राजनेता ज़्यादातर सिर्फ असहमत होने पर ही सहमत होते हैं।

चालाक नेता जनता की राय को अपने फ़ायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करना साध चुके हैं। गंभीर मुद्दों को मीडिया के जरिये आसान लगते हुए बना दिया जाना भी इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। प्राइवेट नैतिकता में एक बड़े झूठ और आधे सच में बहुत फ़र्क होता है। मगर सार्वजनिक नैतिकता में दोनों के बीच की दूरी अक्सर गायब रहती है। सिर्फ वही लोग बड़े झूठ का सहारा नहीं लेते जो पहले से ही ऊँचे राजनीतिक पद पर हैं, जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, वे भी ऐसा ही करते हैं। मीडिया से भी अफ़रा-तफ़री का माहौल का आभास देता हुआ साँपट ऑफ़ियन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। सब राजनेता जान गए हैं कि हाई ऑफ़ियर वोट खींचने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है उसी प्रकार नैतिकता की इस समस्या का समाधान भी संभव है। सबसे पहले समाज को बदलना पड़ेगा। उसे पुराने सामंती चोले से बाहर निकालना होगा। ऐसे चुनावी सुधारों करने होंगे जिससे राजनीति में धन और अपराध का प्रभाव कम किया जा सके। प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी। सूचना का अधिकार, डिजिटल प्रशासन और स्वतंत्र जांच संस्थाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ-साथ समाज में नैतिक शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। जब नागरिक जागरूक होंगे और बेईमान नेताओं को चुनौती देंगे, तभी राजनीति की दिशा बदल सकेगी। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और यदि नैतिकता कमजोर पड़ती है तो शासन व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसे ठीक से समझने वाले विवेकशील नागरिक बनें तो समाज जरूरी है कि नेता, प्रशासक और नागरिक सभी मिलकर ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को मजबूत करें, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सके।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

भारत-अमरीका ट्रेड डील : सार्वभौम देश के राष्ट्रीय हित



रामनिवास बैरवा

यूरोपियन यूनियन के साथ हुए व्यावसायिक समझौते के बाद संयुक्त राज्य अमरीका से अपरिपक्व अन्तरिम व्यापारिक समझौते का सरकारी स्तर और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इस तरह से प्रचार किया गया जैसे अमरीका को जीत लिया हो। व्यापारी और पैसे के हिसाब-किताब में पक्का अमरीका अन्तिम समझौते को किस रूप में सामने लायेगा। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि उस अन्तिम समझौते में भारत अमरीका की शर्तों को मानकर भारत के राष्ट्रीय हितों की हिफाजत कर पायेगा या नहीं। कहीं फजीहत नहीं हो जाये? इसे आगे देखा बाकी है।

2019 में प्रकाशित मेरी पुस्तक "अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का साम्राज्य" में मैंने यह उल्लेख किया था कि अंग्रेजों ने सीधे तौर पर और 'एटलिंग एरिया' के माध्यम से भारत की सम्पत्ति को ब्रिटेन में ले जाया गया था और भारत के व्यापारिक लाभ को लंदन के बैंकों में जमा करवाया गया था। आज संयुक्त राज्य अमरीका अपनी मुद्रा डॉलर के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था बना चुका है। बहुप्रचारित वर्तमान व्यापार समझौता उसी का एकरूप है- जिसमें कृषि की बात को लेकर भारत सरकार को बड़े मंत्री, इस समझौते के शिल्पकार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर अनभिज्ञता बना चुके हैं कि क्या शर्तें हैं। इस प्रकार की अनभिज्ञता कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1935 में ही भारतीय राजनेताओं की अविश्वसनीयता को रेखांकित कर चुकी थी जो आज भी भारत की सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर सवाल खड़े करती है।

इसका कारण भी रहा है- 1947 के पहले पूरे आन्दोलन में सिर्फ दो ही व्यक्ति भगत सिंह और डॉ. भीमराव अम्बेडकर ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा रखी थी। इनके अलावा कोई भी ऐसा राजनेता नहीं था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा पेश की हो। यही कारण है कि 1947 के बाद के वर्षों में न तो इंग्लैंड और न ही अमरीका ने भारत में आर्थिक निवेश किया था और ना ही औद्योगिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया। यूरोपीय देश और जापान युद्ध में तबाही से उबर कर अपने-अपने पुनर्निर्माण में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ़ माफ़, मध्य पूर्व के लाभभग सभी इस्लामिक देशों ने कभी भी भारत पर विश्वास नहीं किया। केवल कूटनीतिक और रणनीतिक कारणों से उन्होंने भारत का समर्थन किया है निवेश कभी नहीं किया। ऐसे में शीत युद्ध की बाधताओं के चलते सोवियत संघ ने आर्थिक और तकनीकी मदद देकर भारत में भारी उद्योगों की नींव रखी थी। इस प्रकार के सरकारी उद्योगों और उद्योगों के सरकारीकरण को राष्ट्रीयकरण बताकर समाजवाद का नाम दिया गया। 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद खुली प्रतियोगिता के नाम पर बिना औद्योगिकरण के विदेशी वित्तीय पूंजी के आयात/निवेश को विकास का मापदंड बना दिया गया। इससे शेरव बाजार में पूंजी लगाना और मुद्रा स्फीति तथा महंगाई बढ़ने पर पूंजी को वापस निकाल लेना बड़े पूंजीवादी साम्राज्यवाद देशों का अपना पूंजी निर्माण तथा वित्तीय साम्राज्य के विस्तार का आधार बन गया। बिना औद्योगिक विकास के चीन जैसे देश का मुकाबला करना भारत जैसे देश में अविश्वसनीय राजनेताओं के अधीन सम्भव नहीं है। अतः अमरीका ने अपनी चिरपरिचित नीति के तहत नेताओं को कई तरह के लालच देकर अपने पक्ष में कहना और खुली अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता के दरवाजे बंद करके अपनी ही शर्तों पर व्यापार करने के लिए बाध्य कराने अमरीकी पूंजीवाद की साधारण रणनीति है।

वर्तमान ट्रेड समझौते के अनुसार, अगले पांच वर्षों में अमरीका के साथ व्यापार को 500 बिलियन डॉलर यानि कि 50 हजार करोड़ डॉलर के स्तर पर

ले जाना है जो कि आज केवल पांच हजार करोड़ डॉलर के स्तर पर है। जाहिर है इतना अधिक व्यापार सामान्य वस्तुओं के व्यापार से सम्भव नहीं है। इसमें तीन क्षेत्रों के व्यापार में अमरीकी एकाधिकार का तत्व छिपा है, और भारत को पूर्णतः अमरीका के आर्थिक उपनिवेश में बदलने की रणनीति है। इसके तहत, सैन्य साजो-सामान पूरी तरह से खरीदा जायेगा, रूस से खरीद पर प्रतिबंध लगाये जायेंगे। रूस और ईरान से खरीदे जाने वाले पेट्रोलियम के बदले अमरीकी कम्पनियों के माध्यम से वेनेजुएला का पेट्रोलियम लेने की बाधता का खुलेआम ऐलान कर ही दिया गया है।

बाकी बचा कृषि क्षेत्र। 2021-22 में सरकार द्वारा बनाये गये तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के अपमान का बदला लेने का रास्ता बना अपनाना अपनाया गया है। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीका के पी.एल. (पब्लिक लॉ) 480 के तहत गेहूँ लेना बंद करके भारत में हरित क्रांति और स्वतंत्र (दूध) क्रांति के परिणामस्वरूप आज भारत खाद्यान्न डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर है। इन्हीं दो क्षेत्रों पर साइलेंट आक्रमण की योजना कथित अमरीकी ट्रेड डील में छिपी है।

उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल, 2025 से पहले भारतीय सामानों पर अमरीकी टैरिफ़ एम.एन.एफ. दर 3 प्रतिशत थी। इससे अमरीका के साथ-साथ भारत का व्यापार बचत में था- यानि कि सरप्लस था। इस पर ट्रम्प ने अपनी संदिग्ध अपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के मालों पर 50 प्रतिशत की दर का डर दिखाकर बाद में 25 प्रतिशत का टैरिफ़ लगाया। अब कथित ट्रेड डील में इसे 18 प्रतिशत किया गया है। साथ ही उक्त ट्रेड डील के प्रस्ताव के साथ ट्रम्प ने एक इक्विक्विटीव आदेश निकाल दिया है, जिसके अनुसार, भारत को जो महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं, वे हैं- भारत रूस से सीधे या इन्डापरेक्लोज़ी पेट्रोलियम खरीदना बंद करेगा (भारत यह तेल रूचये में खरीदता है), भारत अमरीका से उर्जा संसाधन तथा रक्षा सहयोग के लिए पाबंद होगा। छिपे तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ़ 50 प्रतिशत ही रहेगा, ऑटो-कॉम्पोनेंट्स पर यह टैरिफ़ 25 प्रतिशत

ही रहेगा। खेती के उत्पादन अमरीका सामान, जैसे लाल ज्वार, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट्स पर रियायतें भारत बहुत दिया धते पहले ही घोषित कर चुका है। अब, कपास तथा डेयरी उत्पादों के आयात से भारत के कपास उत्पादन और डेयरी उत्पादों की आत्मनिर्भरता प्रभावित होगी। बीच-बीच में यह भी खबरें आई थी कि अमरीका डेयरी उत्पादन उन गाँवों से प्राप्त होता है जिन्हें गाँवों के एनीमल फीड में मांस मिलाकर दिया जाता है, जिससे ज़्यादा दूध का दोहन हो सके।

वास्तव में अगले पांच वर्षों में भारत 500 बिलियन डॉलर के व्यापार के लिए व्यापार-क्या खरीद लेगा और उनका उपयोग कहाँ करेगा? यह प्रश्न आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु बनने में, तथा 05 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था बनने में कितनी सहायक होगी, यह भविष्य ही बतायेगा।

उक्त कथित अन्तरिम समझौते को लेकर अखबारों में छपी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी- "मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करना अच्छा लगा। भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत का टैरिफ़ का अपनी अधिकारता का बखान करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर किसी देश ने अमरीका के साथ किये गये टैरिफ़ घटाए तो फिर से बात करने की कोशिश की तो और भी बुरा हो सकता है। भारत के अमरीका परस्त नेताओं, मंत्रियों के पास क्या जवाब होगा सिवाय इसके कि भारत की वेनेजुएला के रास्ते ले जाया जाये। लेकिन भारत में, कहने को तो न्यायपालिका और संसद स्वाधिकारी, स्वतंत्र हैं, परन्तु कार्यकारिणी प्रमुख की रीतियों, नीतियाँ, अन्तर्राष्ट्रीय संवाद समझौतों के बारे में कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकती; उनका अनुमोदन करने को अपने अधिकार में लेने के संसद के पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में भारत की सार्वभौमिकता, आर्थिक-औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा अमरीका के साथ होने जा रही ट्रेड डील से क्या सुरक्षित और संरक्षित हो पायेगी?"

वैसे, 2029 में ट्रम्प भी राष्ट्रपति नहीं होगा और भारत भी आम चुनावों के दौर से गुजरेगा।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

जब नागरिक जागरूक होंगे और बेईमान नेताओं को चुनौती देंगे, तभी राजनीति की दिशा बदल सकेगी। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और यदि नैतिकता कमजोर पड़ती है तो शासन व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसे ठीक से समझने वाले विवेकशील नागरिक बनाने के प्रयास जरूरी हैं।

में बिगड़ते चले गए और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होने के बजाय आजादी के पहले की परंपरागत सामंती छाया में सुकून पाती रही। सवाल उठाना जा सकता है कि राजनेता जैसे हैं, वैसे क्यों हैं? यह जानने के लिए कभी गंभीरता से बुद्धिजीवियों ने विचार ही नहीं किया। इस पर भी नहीं कि राजनीतिक प्रक्रिया गंदे लोगों को कैसे या क्यों ऊपर उठा लाती है। समाज की भूमिका और उसके सामान्य सरोकारों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होती। समाज और उसे चलाने वाले धर्म के नेता भी वर्तमान में बिगड़ल राजनेताओं की होड़ करने में लगे नज़र आते हैं। मगर सभी बुराइयों का दोष राजनेताओं पर डाल देना इस मुद्दे से बचना है। होशियार छात्र या प्रोफेसर जो घर पर कम सैलरी वाली नौकरी के बजाय विदेश में आरामदायक नौकरी पसंद करते हैं, भरपूर प्रैक्टिस करने वाले वकील और डॉक्टर अक्सर अपनी आय छिपाने में नहीं हिचकित करते, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो पागलों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पाने की कोशिश करते हैं, व्यापारी जो जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है और सही कनेक्शन वाला आदमी सब सेवाएँ पा जाता है मगर कमजोर व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं के लिए लाइन में लगा रह जाता है। यह भी कैसी नैतिकता है। समाज के सभी हिस्सियदार लोग क्या विधानमंडलों में बैठे अपने प्रतिनिधियों जितने ही नैतिक रूप से कमजोर नहीं हैं? सच तो यह है कि राजनेता उसी भ्रष्ट सामाजिक माहौल में बढ़ते हैं जिसमें दूसरे समूह फलते-फूलते हैं। बस सबको चाहें अलग-अलग होती है। लोकतांत्रिक राजनीति की अपनो ज़रूरत होती है, जिसे सबसे जरूरी है, प्रचलित रूढ़ानों को फाँलो करना, मौजूदा बकवास को दोहराना, लोकप्रियता और पब्लिसिटी के लालच में पड़ना है। यह बुलंद किया जाता है कि नारे लगाने वाली आवाज़ें कितनी भी ज़्यादा और जोरदार क्यों न हों बकवास बकवास ही रहती है। इसलिए, अगर आजकल के मीडिया बकवास से परे हों, अगर राजनेता आखिरी मिन्ट में राजनीतिक वफादारी बदल लेते हों और अगर नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के फायदे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताते जाते हों, तब आन आदमी निराश होकर अपने हाथ खड़े न करे तो क्या करे। वर्तमान में बदले की भावना वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति है। किसी राजनेता से इससे बचने की उम्मीद किसी को नहीं रही है। राजनेता ज़्यादातर सिर्फ असहमत होने पर ही सहमत होते हैं।

चालाक नेता जनता की राय को अपने फ़ायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करना साध चुके हैं। गंभीर मुद्दों को मीडिया के जरिये आसान लगते हुए बना दिया जाना भी इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। प्राइवेट नैतिकता में एक बड़े झूठ और आधे सच में बहुत फ़र्क होता है। मगर सार्वजनिक नैतिकता में दोनों के बीच की दूरी अक्सर गायब रहती है। सिर्फ वही लोग बड़े झूठ का सहारा नहीं लेते जो पहले से ही ऊँचे राजनीतिक पद पर हैं, जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, वे भी ऐसा ही करते हैं। मीडिया से भी अफ़रा-तफ़री का माहौल का आभास देता हुआ साँपट ऑफ़ियन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। सब राजनेता जान गए हैं कि हाई ऑफ़ियर वोट खींचने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है उसी प्रकार नैतिकता की इस समस्या का समाधान भी संभव है। सबसे पहले समाज को बदलना पड़ेगा। उसे पुराने सामंती चोले से बाहर निकालना होगा। ऐसे चुनावी सुधारों करने होंगे जिससे राजनीति में धन और अपराध का प्रभाव कम किया जा सके। प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी। सूचना का अधिकार, डिजिटल प्रशासन और स्वतंत्र जांच संस्थाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ-साथ समाज में नैतिक शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। जब नागरिक जागरूक होंगे और बेईमान नेताओं को चुनौती देंगे, तभी राजनीति की दिशा बदल सकेगी। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और यदि नैतिकता कमजोर पड़ती है तो शासन व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसे ठीक से समझने वाले विवेकशील नागरिक बनें तो समाज जरूरी है कि नेता, प्रशासक और नागरिक सभी मिलकर ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को मजबूत करें, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सके।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में तालाबंदी कर देनी चाहिए ?



प्रो. अशोक कुमार

आज भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे दौराहट पर खड़ी है जहाँ उसकी उपयोगिता और अस्तित्व दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। देश के कोने-कोने में कुकुरमुत्तों की तरह उगे महाविद्यालय और दशकों पुराने विश्वविद्यालय आज डिग्री बाँटने वाले केंद्रों में तब्दील हो चुके हैं। कक्षाओं में पसरा सन्नटा, परीक्षाओं के समय वन वीक सीरीज और 24 ऑवर सीरीज के लिए उमड़ती भीड़, और संस्थानों का गहराता आर्थिक संकट-ये सब एक ऐसी दुर्गंध की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। ऐसे में यह तीखा सवाल उठाना लाजिमी है: क्या उन संस्थानों को बंद कर देना चाहिए जो न ज्ञान दे रहे हैं और न ही रोजगार?

मर्ज की गहराई:- भारत की उच्च शिक्षा का सबसे त्रासद पैलू कक्षाओं की रिक्तता है। छात्र प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन उनका कॉलेज से वास्ता केवल परीक्षा फॉर्म भरने या डिग्री लेने तक सीमित रह गया है। इसके पीछे

एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण है। छात्र को यह भली-भाँति ज्ञात है कि जो पाठ्यक्रम उसे पढ़ाया जा रहा है, जब दशकों पुराना है और बाजार की जरूरतों से उसका कोई सरोकार नहीं है। जब कक्षा में मिलने वाला ज्ञान उसे रोजगार की गरंटी नहीं देता, तो वह अपनी ऊर्जा और समय शीटकट याने कुर्जी या सीरीज संस्कृति में लगाता है।

यह सीरीज संस्कृति शिक्षा के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा खिलवाड़ है। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए था, वहाँ मात्र 100-200 पन्नों की रटी-रटाई सामग्री ने बौद्धिक विकास का गला घोट दिया है। परीक्षा प्रणाली की विफलता ही है कि एक छात्र साल भर गायब रहकर भी मात्र 24 घंटे पढ़कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसे में शिक्षा केवल एक कागजी रसम बनकर रह गई है।

आर्थिक बदहाली और नियुक्तियों की कमी संस्थानों के बंद होने की वकालत करने वालों का एक बड़ा तर्क उनकी आर्थिक स्थिति है। सरकारी कॉलेजों में बजट की भारी कमी है, तो निजी संस्थान केवल मुनाफे के मॉडल पर चल रहे हैं। बुनियादी ढाँचे के नाम पर टूट रही हैं बेंचें, पुरानी प्रयोगशालाएँ और धूल फाँकती लाइब्रेरी रह गई हैं। सबसे भयावह स्थिति नियुक्तियों की है। दशकों से कई राज्यों में प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। अतिथि विद्वान या एडहॉक या संबल

योजना व्यवस्था के भरोसे चल रही शिक्षा व्यवस्था से गुणवत्ता की उम्मीद करना बेमानी है। शिक्षक को पेंशन की गरंटी नहीं! जब शिक्षक का अपना भविष्य अनिश्चित हो, तो वह छात्रों के भविष्य की नींव कैसे मजबूत करेगा?

रिक्त पदों और धन के अभाव ने विश्वविद्यालयों को शोध के बजाय केवल परीक्षा आयोजित करने वाली मशीन बना दिया है। यही कारण है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय संस्थान अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते दिखते हैं।

क्या तालाबंदी ही एकमात्र विकल्प है?

तर्क दिया जाता है कि यदि कोई फ़ैक्ट्री उत्पाद नहीं दे रही और घाटे में चल रही है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या शिक्षा पर भी यही मार्केट लॉजिक लागू किया जा सकता है? कतई नहीं!

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक ज़ासदी का आमंत्रण होगा। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:- **शिक्षा का लोकतंत्रीकरण:** भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ आर्थिक असमानता चरम पर है, सरकारी कॉलेज ही गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा का एकमात्र द्वार है। इन्हें बंद करने का अर्थ होगा शिक्षा को केवल अमीर की जागीर बना देना।

सामाजिक चेतना के केंद्र: विश्वविद्यालय केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, वे समाज को नेतृत्व देते हैं। युवाओं के भीतर वैचारिक मंथन और

तर्क करने की क्षमता वहीं विकसित होती है। संस्थान बंद होने से देश में बौद्धिक शून्यता पैदा हो जाएगी। **डोमोग्राफिक डिफ़िडेंस का संकट:** भारत के पास युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। यदि हम संस्थानों को सुधारने के बजाय बंद करेते, तो यह जनसांख्यिकीय लाभार्थ देश के लिए जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा। बिना कौशल और शिक्षा के भटकते युवा अराजकता की ओर बढ़ सकते हैं।

समाधान: बंद करना नहीं, री-इंजीनियरिंग अनिवार्य है। हमें संस्थानों के ताले लगाने के बजाय व्यवस्था के इंजन को बदलने की जरूरत है। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ कड़े और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे:-

पाठ्यक्रम का मार्केट-लिंक होना: हर डिग्री के साथ एक वोकेशनल स्किल अनिवार्य होनी चाहिए। यदि कोई छात्र साहित्य पढ़ रहा है, तो उसे कंटेंट राइटिंग या अनुवाद का कौशल सिखाया जाए। यदि कोई विज्ञान पढ़ रहा है, तो उसे स्थानीय उद्योगों के साथ इंटरैक्शन करना अनिवार्य है।

परीक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव: जब तक प्रश्नचरम रटने वाले होंगे, सीरीज बिकती रहेगी। परीक्षाओं को ओपन बुक बनाया जाए, प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन हो और कक्षा में उपस्थिति को केवल कारगर्ज पर नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से सुनिश्चित कर उसे क्रेडिट स्कोर से जोड़ा जाए।

नियमित नियुक्तियाँ और जवाबदेही: सरकार को शिक्षा पर

जीडीपी की क्षमता एक हद्द हिस्सा खर्च करना ही होगा। रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए, लेकिन साथ ही शिक्षकों की जवाबदेही भी तय हो। शिक्षकों का स्टूडेंट फीडबैक और रिसर्च आउटपुट उनकी पदोन्नति का आधार होना चाहिए।

उद्योग-अकादमिक तालमेल : महाविद्यालयों को अपने क्षेत्र के उद्योगों के साथ जुड़ना होगा। उद्योग अपनी जरूरत बताएँ और कॉलेज उस अनुसार प्रशिक्षण दें। इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा और छात्रों को प्लेसमेंट भी मिलेगा।

निष्कर्ष-उच्च शिक्षा में व्याप वर्तमान संकट व्यवस्था की विफलता है, शिक्षा के महत्व की नहीं। छात्र का कक्षा में न आना कॉलेज की असफलता है कि वह छात्र को कुछ नया नहीं सिखा पा रहा। वन वीक सीरीज का फलना-फूलना हमारी परीक्षा प्रणाली पर एक तमाचा है। संस्थानों को बंद करना पलायनवाद है, सुधारवाद नहीं।

हमें कॉलेजों को डिग्री छापने वाली प्रेस के बजाय स्किल और विज्ञान देने वाले पावरहाउस में बदलना होगा। यदि हम आज इन संस्थानों को सुधारने के लिए निवेश नहीं करेंगे, तो कल हमें जेलों और बेरोजगारी पतनों पर कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। शिक्षा बोझ नहीं, बल्कि कर्षण का निवेश है। जरूरत है कि हम इमारतों पर नहीं, शिक्षा की आत्मा-यानी शोध, न्यायकार और गुणवत्ता-पर ध्यान केंद्रित करें।

प्रो. अशोक कुमार, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

राशिफल

बुधवार 11 मार्च, 2026

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:00 तक, वज्र योग प्रातः 9:12 तक, बालव करण दिन 3:07 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:00 से धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरु-

मिथुन, शुक-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज यमघट योग रात्रि 10:00 से सूर्योदय तक है। आज गुरु मार्गी प्रातः 9:00 से होगा। आज शीतला माता पूजन बास्वोद्य है। आज कालाष्टमी, ऋषभ देव जयन्ती, वर्षांतप आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:41 तक, शुभ 11:09 से 12:37 तक, चर 3:33 से 5:01 तक, लाभ 5:01 से सूर्यास्त तक। **राहुकाल:** 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:45, सूर्यास्त 6:29

मेघ
अपनी कार्य योजना सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक परेशानियाँ अभी यथावत बनी रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आज ध

स्पीकर देवनानी द्वारा संसदीय संस्कृति में किये गए नवाचारों से लोकतंत्र में आमजन की आस्था बढी : मुख्यमंत्री

संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत है और विपक्ष के सुझावों पर विचार किये जाना भी आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा अधिक दिनों तक और नियमों व परम्पराओं से चल रही है। हम सभी का भी एक ही ध्येय होता है कि राजस्थान की जनता का भला किस प्रकार से किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पीकर वासुदेव देवनानी द्वारा विधान सभा में किये गये नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि विगत दो सालों में पुस्तकें लिखकर उन्होंने संसदीय परम्पराओं के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जो परम्परा रही है वह बहुत ही ऐतिहासिक और संसदीय मूल्यों पर आधारित है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक "संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि" के नवीन संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर स्पीकर देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा राजस्थान विधान सभा में किये गये नवाचारों पर आधारित पुस्तक "संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि" के नवीन संस्करण कृति के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। उन्होंने स्पीकर देवनानी की दोनों पुस्तकों का अनावरण कर विमोचन किया और उत्कृष्ट लेखन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह समारोह

के साथ मनाया जायेगा। विधानसभा में सतत यात्रा का उत्सव है। लोकतांत्रिक संस्थाएँ तब ही सशक्त बनती हैं जब वे परम्पराओं और नवाचारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जन भागीदारी, पादशिता को केंद्र में रखकर कार्य करती हैं। वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह

50 हजार से अधिक लोगों ने देखा विधान सभा का संग्रहालय : देवनानी

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में सेन्ट्रल हॉल का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 14 करोड़ रुपये की राशि भी बजट में पारित कर दी है। देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए भी राज्य सरकार द्वारा बजट में राशि का प्रावधान किये जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा के नवाचारों में बजट की कोई कमी नहीं रखने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में संविधान गैलरी, वन्दे मातरम की 150वीं जयन्ती पर वन्दे मातरम दीर्घा और कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कर नवाचार किये गये हैं। अब आने वाले समय में विधान सभा में कोई भी प्रश्नों के जवाब लिखित नहीं रहेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि जनहित के मुद्दों को हल करने के लिए विधायकों द्वारा लाये गये प्रश्नों के जवाब 100 प्रतिशत मांगवाये जाए।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा सदन का आसन महत्वपूर्ण होता है। आसन पर बैठने के बाद वे अनुशासन और नियमों के प्रति कठोर

हो जाते हैं। सदन से किसी सदस्य को अनुशासनहीनता के मामले में जब सदन से बाहर कर दिया जाता है तो उनकी स्थिति उस मां की तरह भी हो जाती है, जिसका बच्चा जब तक भोजन नहीं कर लेता है तब तक वह दुःखी रहती है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधान सभा का शत्रु सनातन रहा है। विधान सभा में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। स्पीकर का संरक्षण ही प्रतिपक्ष को मजबूती प्रदान करता है।

जूली ने कहा कि स्पीकर देवनानी की सेन्ट्रल हॉल निर्माण की सोच सराहनीय है। यहाँ पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य बैठकर चर्चा कर सकेंगे और उन सभी में आपसी समन्वय की भावना भी प्रबल हो सकेगी। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि स्पीकर देवनानी ने दो वर्षों में विधान सभा में अनेक नवाचार किये हैं। विधान सभा संग्रहालय को देखने आने वालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि विधान सभा से आमजन का जुड़ाव बढ़ रहा है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आभार जताते हुए कहा कि समारोह में मंत्रीमण्डल के सदस्य, विधायक, जनप्रतिनिधि, कुलगुरु, शिक्षाविद सहित गणमान्य लोग मौजूद थे।

दो से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे मेयर-पार्षद

कुष्ठ रोग पीड़ित भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता अब पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बन सकेंगे। विधानसभा में मंगलवार को बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को पारित कर दिया। सरकार ने एक्ट की धारा 18 (2) में संशोधन किया है। दो बच्चों की बाधता साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई गई है। अब इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून बन जाएगा। अगले निकाय चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे।

■ **यूडीएच मंत्री बोले**
"निकायों में हम 'एक राज्य-एक चुनाव' करवाने की हालत में हैं, सिर्फ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।"

■ **अगर आप विपक्ष मांग लिखकर देता है कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव कटा लिए जाएं, तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे।**

■ **कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सदन में पूछा कि "क्या केंद्र-राज्य की योजनाओं से भी दो बच्चों की बाधता हटाएंगे?"**

अगर आप विपक्ष के लोग मांग करते हैं और लिखकर देते हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव करावा जाए तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे। नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में दो से ज्यादा बच्चों वाली को लाभ नहीं मिलता। अब निकाय और पंचायतीराज चुनावों में आपने दो बच्चों की बाधता हटा दी है तो क्या अब केंद्र-राज्य की योजनाओं में भी इस बाधता को हटाएंगे? दर्जनों ऐसी योजनाएँ हैं, जहाँ तीसरा बच्चा होने पर लाभ से वंचित कर दिया जाता है। उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का फैसला दिया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव करवाने की नीयत नहीं है। अब आप चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का बहाना बना रहे हैं कि आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा। उधर, आयोग को मना कर रखा है कि रिपोर्टें नहीं देनी हैं। आयोग कह रहा है कि सरकार डेटा नहीं दे पा रही है। सरकार डेटा नहीं दे पा रही है तो यह उसकी विफलता है।

कल पंचायतीराज मंत्री कह रहे थे कि सब जागरूकता आ गई, दो बच्चों की बाधता की जरूरत नहीं है। जब यह सब हो गया तो फिर योजनाओं से भी बाधता हटाइए। डोटासरा ने कहा कि चुनाव के लिए आप नगरपालिका एक्ट

'60 दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वतः जमानत का अधिकार नहीं'

न्यायिक अधिकारी तय अवधि में निस्तारण का प्रयास करें : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत जमानत का स्वतः लाभ इस आधार पर नहीं मिल सकता कि गैर जमानती मामले में साक्ष्य दर्ज करने के प्रथम दिन से साठ दिन में प्रकरण तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की

एकलपीठ ने यह आदेश अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा है कि वह ऐसे मामलों को तय अवधि में तय करने का प्रयास करें। जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में साल 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी और वह गत 25 मई से न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में कहा

गया कि गत 18 अगस्त को निचली अदालत उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इसके बावजूद किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए, जबकि बीएनएसएस की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत यदि गैर जमानती मामले में आरोप तय होने के 60 दिन में सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। मई से न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में कहा

एमएस शेखावत ने कहा कि उसने पीड़ित को ग्राफिट ट्रेडिंग प्लान का लालच देकर उसके करीब 82 लाख रुपए की टागी की है। वहीं उसके खिलाफ अन्य मामले में लंबित है। धारा 480 की उपधारा 6 को अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता और अदालत परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर निर्णय कर सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

46.30 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर। अशोक नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलर प्रोजेक्ट की आठ में फर्जी बैंक गारंटी लगाकर 46 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनिश्चित तरीके से फर्जी बैंक गारंटी तैयार कर सरकारी संस्था से बड़ी रकम हड़प ली थी। डीसीपी (दक्षिण) उपायुक्त राजीव राज ने बताया कि मुख्य आरोपी महेश भाई (50) गुजरात के अहमदाबाद का निवासी है और फिलहाल इंदौर में रह रहा था।

फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल जैसे मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर जारी नकली मेडिकल प्रमाण पत्र जारी होने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर नकली प्रमाण पत्र बनाने और इन्हें जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे चिकित्सा प्रमाण पत्रों को ऑन लाइन पोर्टल के जरिए

जारी करने के संबंध में लंबित फाइल पर 45 दिन में फैसला करें। अदालत ने कहा कि इसके अनुमोदन के लिए विभाग के संबंधित अधिकारियों से परामर्श कर अंतिम रूप दें। वहीं अदालत ने मामले में बनाए एसओपी के ड्राफ्ट की कॉपी भी अदालत में पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शकुंतला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने

अदालत को बताया कि ऐसे प्रमाण पत्रों की जालसाजी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर उसे अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। इस पर अदालत ने इसे अंतिम रूप देने के लिए 45 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि प्रकरण एनबीसी के पास स्थित करीब छह बीघा जमीन से जुड़ा हुआ है। जिसके स्वामित्व को लेकर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश हुए थे। वहीं कानूनी कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता की

स्मारकों- संग्रहालयों में 18 मार्च को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश

जयपुर। राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने अपने अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 18 मार्च, निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की है। निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग डॉ. पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में 7 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है एवं लेटर पैड हस्ताक्षर युक्त पत्र के साथ आने वाले शिक्षक संस्थाओं को भी पूरे सप्ताह स्मारकों और संग्रहालयों में निःशुल्क भ्रमण करवाया जाता है।

राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन

मंडियों और पार्कों का तेजी से होगा विकास, भूमि अर्जन प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सुव्यवस्थित : मुख्यमंत्री

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने दिशा में राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मण्डी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से मण्डी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत पर रोक बरकरार रखते हुए इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों में दखल से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन इलाकों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और ट्रैफिक के नियमन से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश फिलहाल प्रभावी रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह संबंधित क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रित करने या जरूरी प्रतिबंध के लिए कानूनी प्रावधानों के

में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इसी प्रकार, भूमि अवाप्ति के ऐसे मामलों जिनमें अवाड जारी नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही, आपसी समझौते से भूमि के अर्जन पर भू-धारकों द्वारा मण्डी समिति को निःशुल्क नवीन भूमि समर्पित करने पर कुल समर्पित भूमि के बराबर 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस नीति से भूमि अर्जन कर उपयुक्त स्थानों पर नवीन याडों का निर्माण तेजी से संभव हो सकेगा। साथ ही, भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने

राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये से अधिक कार्यों की स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, अटल (बारा), बारा, रामगंजमण्डी (कोटा), गुलाबपुर (भीलवाड़ा), गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर), सुजानगढ़ (चूरू), दूदू (जयपुर), सरदारशहर (चूरू) एवं सूरजपोल, (अनाज) जयपुर सहित अन्य मण्डियों में याई निर्माण, विद्युत संबंधी एवं सार्वजनिक सड़कों के निर्माण कार्य करवाए जायेंगे। इन कार्यों से व्यापारियों एवं किसानों के लिए मण्डी प्रांगणों में मूलभूत सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

'छात्रावासों में चौकीदार-रसोइयों संवेदक से जाँच बेसिस पर लेते हैं'

जयपुर (कासं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संवेदक द्वारा जाँच बेसिस पर रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएँ ली जाती हैं। मंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में दिए गए उत्तर में विभाग के स्वीकृत पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी। विभाग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त नहीं है। हालांकि, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था को प्रभावित न होने देने के लिए स्थानीय स्तर पर मानदेय अथवा समय-आधारित व्यवस्था के माध्यम से संवेदक द्वारा रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएँ ली जाती हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में रसोइयों एवं चौकीदारों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध अंशकालीन रसोइयों या चौकीदार कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग के राजकीय छात्रावासों में वित्त विभाग की सहमति उपरान्त रसोइयों व चौकीदार का कार्य आरटीपीपी एक्ट के मुताबिक जाँच बेसिस पर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने हैल्पलाइन पर सुनी समस्याएं

लाखेरी के पंकज सुमन की शिकायत पर बूंदी कलेक्टर को मौके पर दिए निस्तारण के निर्देश

जयपुर । राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन (181) आमजन की समस्याओं का अंतिम पड़ाव साबित हो रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन



वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया।

■ **10261 प्रकरणों का निस्तारण, औसतन 27 दिनों में हो रहा समस्याओं का समाधान**

(181) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा परिचायियों से सीधे संवाद कर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण कर कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव के परिचायियों से संवाद के दौरान बूंदी जिले के लाखेरी के पंकज सुमन द्वारा बताया गया कि मेन रोड पर लगे पीपल के पेड़ मे से गुजर रही बिजली लाइन आमजन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मौके पर ही बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदार को फोन

कर मंगलावर शाम से पहले परिचायी की समस्या के समाधान कर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीकर के महेश कुमार खुडानिया ने समस्या के समयबद्ध समाधान हो जाने पर राज्य सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर के श्री विष्णु द्वारा दर्ज केमिकल फेक्ट्री से प्रदूषण की शिकायत पर आनंद कुमार ने संबंधित अधिकारी को आंचक निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई के निर्देश

दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्याओं का अंतिम पड़ाव होना चाहिए। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित कुल 10957 प्रकरण दर्ज

हुए, जिनमें से 10261 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि 27 दिन है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों में राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन पर स्वयं उपस्थित रहकर परिचायियों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं।

'दिलावर-डोटासरा की जोड़ी स्पোর্स साइकोलॉजी में आ सकती है'

जयपुर (विसं)। महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी बिल पर बहस का जवाब देते हुए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री ग्रेसन दिलावर पर चुटकी ली। मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि आजकल एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट लगाते हैं। स्पোর্स साइकोलॉजिस्ट बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ी को टिप्स देते हैं। उसे पता होता है कि क्या चीज करनी है, जिससे शानदार प्रदर्शन करे। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरे क्षेत्र के विधायक को देखकर विधायक में उत्तेजना

■ **खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह ने सदन में दोनों नेताओं पर चुटकी ली**

जाती है यह साइकोलॉजी होती है, यह सारी की सारी चीजें जुड़ती हैं, तब जाकर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। जैसे डोटासराजी और मदन दिलावरजी की जो जोड़ी है, वो स्पোর্स साइकोलॉजी में आ सकती है, यह उदाहरण ठीक है न। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी कहा कि दोनों को साथ में खाना खिला दीजिए।

अजमेर में दो युवकों पर हमले से आक्रोशित वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया

वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलैक्ट्रेट पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की

अजमेर, (कासं)। शहर में वाल्मीकि समाज के दो युवकों पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग डाक बंगले से रैली के रूप में कलैक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना देकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि आक्रोशित लोगों ने कलैक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगी बैरिकेडिंग हटाकर परिसर में प्रवेश कर लिया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ उग्र होने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया। बाद में पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। इसके बाद समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एकरा हो गए और आरोपियों की तलाक गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने पर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने



अजमेर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।

समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उन्हें शांत किया और मामले में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि अनिल नरवाल ने बताया कि 8 मार्च की रात करीब 11 बजे गुलाबबाड़ी नाना मदार फाटक क्षेत्र में समाज के दो युवक रघुवीर और अर्जुन किसी

काम से जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर लाठी, सरिया, चाकू सहित अन्य हथियारों से लैस थे और उन्होंने दोनों युवकों को धरकर मारपीट की। प्रतिनिधियों के अनुसार हमले में रघुवीर के पैर की हड्डी टूट गई है, जबकि अर्जुन को शरीर में अंदरूनी चोटें आई

अपमानित किया। आरोप यह भी लगाया गया कि हमलावरों ने डर फैलाने के लिए रिवाल्वर से हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार हमले में रघुवीर के पैर की हड्डी टूट गई है, जबकि अर्जुन को शरीर में अंदरूनी चोटें आई

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

हैं। दोनों का उपचार कराया जा रहा है। घटना को लेकर समाज में काफी रोष व्याप्त है। इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

अजमेर में वाल्मीकि समाज के दो युवकों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हमले कोली और मंथन यादव को गिरफ्तार में लिया है।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वाल्मीकि समाज द्वारा प्रस्तावित अलवर गेट थाने के घेराव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उदयपुर : वृद्ध का अपहरण करने वाले नौ आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के बड़गांव थाना पुलिस ने जमीन हथियाने के लिए वृद्ध का अपहरण करने वाले नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि बदमाश गिराह बनाकर रजिस्ट्रीयों करवाते हैं, जिसके कागजात पहले से ही तैयार कर रखते हैं। बदमाशों ने रैकी कर योजना के चलते रामा का अपहरण किया, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस के सक्रिय होने पर पकड़े जाने के भय से रामा को साईफन पर छोड़ कर फरार हो गए। किशन मेघवाल निवासी बांसलिया नान्देशमा सायरा व सुरेश मेघवाल निवासी सुहावतो का गुड्डा गोमुन्दा के कहने पर आरोपियों ने रामा का अपहरण किया था। पुलिस किशन, सुरेश व साथियों की तलाश कर रही है।

प्रकरण के अनुसार 8 मार्च को बंशीलाल पुत्र रामलाल गमेती निवासी हलेलाल नारायण सेवा संस्थान के पास बडगांव ने रिपोर्ट दी कि सबसे में काम

पुलिस के सक्रिय होने पर पकड़े जाने के भय से वृद्ध को छोड़ कर फरार हो गए थे

से गया था। मेरी मां कंकू बाई व पिता रामा घर पर थे। पिता पास में स्थित पनचट पर पानी लेने गए थे, जहां पर आई कार में सवार बदमाश मुकेश पुत्र मांगीलाल गमेती निवासी लियो का गुड्डा व नन्दु गमेती निवासी शौभागपुरा व विजय कुमार निवासी लखावली व एक अन्य व्यक्ति मेरे पिता का कार में डाल कर अपहरण कर ले गए। आरोपी मेरे पिता के नाम की जमीन हथियाने की नियत से अपहरण कर ले गए।

इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर बडगांव थानाधिकारी किताब देवी के नेतृत्व में गठित दल ने

मामले में अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर रामा गमेती को दस्तयाव कर बदमाशों की तलाश कर मामले में मुकेश गमेती पुत्र मांगीलाल गमेती निवासी हाथीवरा बडगांव, अशोक बंजारा पुत्र धंरलाल बंजारा निवासी ईसवाल गोमुन्दा, दीपचन्द्र पुत्र लक्ष्मीलाल गमेती निवासी खरबडिया हिरणमगरी, सुरेश पुत्र लोगर गमेती निवासी काठबा गोमुन्दा, पुष्कर गमेती पुत्र मेघाली निवासी पडियारों का गुड्डा सुखेर, विजय गमेती पुत्र लालराम गमेती निवासी पावटा लखावली सुखेर, प्रकाश गमेती पुत्र तख्ता राम गमेती निवासी बीएसएनएल टावर के पास गोमुन्दा, प्रवीण पुत्र पन्नालाल मेघवाल निवासी बांदरावाड़ा गोमुन्दा हॉल आरामश्रीन की गली बडगांव तथा दिलीप कुमार गमेती पुत्र मोहनलाल गमेती निवासी गोडान कला नाई को गिरफ्तार इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की।

हमलावरों ने एटीएम में युवक से लूटपाट की

गंगापुर सिटी, (निर्सं)। अपराधियों में पुलिस के भय नहीं होने से आमजन का जीना दुश्चारा हो रहा है। कुछ ऐसा ही मामला मंगलवार को देखने को मिला, जिसमें नगर परिषद गंगापुर सिटी के कर्मचारी राहुलराम पुत्र सोमवार से सोमवार शाम एटीएम से 1.5 हजार रुपए छीन लिए गए। यह घटना हीरालाल की मौल के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा

के एटीएम पर हुई। राहुलराज ने बताया कि सोमवार को शाम को वह एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, तभी खुशीराम पुत्र कजोड़मल, किशन पुत्र खुशीराम और बेदराम पुत्र कजोड़मल नामक 3 आरोपी उनके पास आए। आरोपियों ने राहुलराज के साथ मारपीट की और 1.5 हजार रुपए छीन लिए। पीड़ित के अनुसार, मारपीट के

दौरान किशन ने उनकी नाक पर पंच मारा, जिससे उन्हें चोट आई और पीट पर लात भी मारी। घटना के तुरंत बाद, पीड़ित राहुलराज ने गंगापुर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और लूट सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

अनूपगढ़ में आवारा श्वानों ने दो साल की बच्ची पर हमला किया

अनूपगढ़, (निर्सं)। यहां गांव 4 ए में मंगलवार दोपहर एक आवारा कुत्ते (श्वान) ने दो साल की बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। गंभीर रूप से घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, हर्षिता (2) अपनी दो बड़ी बहनों प्रीता (5) और हिमांशु (4) के साथ आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौट रही थी। घर से लगभग 200 मीटर पहले एक आवारा कुत्ते ने हर्षिता पर अचानक हमला कर दिया। हर्षिता की दोनों बहनें भागकर घर पहुंचीं और

कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला, गंभीर घायल बच्ची को बीकानेर रेफर किया

दो बड़ी बहनों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौट रही थी बच्ची, रास्ते में हुई घटना

परिवार को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही हर्षिता की दादी राजू देवी और गांव के युवक विनोद कुदावला मौके पर पहुंचे। उन्होंने हर्षिता को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। हर्षिता को तुरंत अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

सरकारी जिला अस्पताल के डॉक्टर केशव कामरा ने बताया कि कुत्ते

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है। विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

निवाई कृषि उपज मंडी में सरसों की बम्पर आवक

निवाई, (निर्सं)। कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक लगातार बढ़ रही है। खेतों से कटाई के बाद किसान सीधे मंडी में पहुंच रहे हैं, जिससे मंडी में रौनक बढ़ गई है। मंगलवार को मंडी में सरसों की रिकार्ड करीब 60-70 हजार बोरी की आवक दर्ज की गई।

व्यापार मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश चंवरिया व ताराचन्द बोहरा ने बताया कि आवक बढ़ने के साथ सरसों के भाव भी बढ़े हैं। सरसों अधिकतम 6351 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकी है। उन्होंने बताया कि निवाई के आसपास के गांवों सहित

चाकसु, बौली एवं पीपलू क्षेत्र से भी किसान सरसों लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। अधिकांश किसानों की फसल कटाई पूरी हो चुकी है और वह खेतों से सीधे मंडी में उपज को लेकर आ रहे हैं।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढ़े तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

अजमेर रेलवे स्टेशन पर बैटरी संचालित कार सेवा का ट्रायल शुरू

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैटरी से चलने वाली कार सेवा का शुरुआत कर दी गई है। यह सेवा विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं तथा बीमार यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में मदद करेगी। फिलहाल इस सेवा को ट्रायल बेस पर शुरू किया गया है और इसके सफल संचालन के बाद इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने

विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं तथा बीमार यात्रियों को राहत मिलेगी

के प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में अजमेर रेलवे स्टेशन पर बैटरी ऑपरेटेड कार सेवा शुरू की गई है। यह कार यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन तक पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि यह बैटरी संचालित कार एक बार में पांच यात्रियों

को ले जाने में सक्षम है। यात्री इस सेवा का लाभ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित हेड टीसी ऑफिस या सहायता बृथ पर संपर्क करके ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जबकि पांच वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए 30 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। फिलहाल एक बैटरी संचालित कार का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

पाक की ओर से ड्रोन से फेंकी गई थी हेरोइन

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर जिले में करीब 32 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से 6 किलो 400 ग्राम फेंकी गई। इसे समेजा कोटी थाना पुलिस और बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए जबाब कर लिया है। साथ ही मामले को जांच शुरू कर दी है। घटना जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव 43 पीएस की है। गांव के एक खेत में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन द्वारा 6 किलो 400 ग्राम फेंकी गई थी। मामले में बीएसएफ ने एक तस्करो को पकड़ा है।

आरोपी हेरोइन की खेप लेने बॉर्डर के पास पहुंचा था, जिसे भारतीय जवानों ने पकड़ लिया। तस्करो पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला है। आरोपी से पुलिस, बीएसएफ और अन्य एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है कि तस्करो हेरोइन को कहाँ ले जाने वाला था और क्या उसके अन्य साथी भी मौके पर थे।

पंजाब के एक तस्करो को पकड़ा, आरोपी के साथ दो अन्य तस्करो भी थे

आरोपी से पुलिस, बीएसएफ और अन्य एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है

साथ ही तस्करो के पूरे नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। इस बीच रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, समेजा कोटी समेत आस-पास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे खेतों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच में सामने आया कि आरोपी के साथ दो अन्य तस्करो भी थे, लेकिन दोनों फरार हो गए। दोनों की तलाश की जा रही है।

गर्मी की दस्तक के साथ ही दौसा में जलापूर्ति की मांग बढ़ने लगी

गर्मी के यही हालात रहे तो इस पर प्रशासन को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है

वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है

दौसा, (निर्सं)। सूरज के तीखे तेवर एवं समय से पूर्व गर्मी के दस्तक दिये जाने के साथ ही जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। इधर तापमान 35 से 40 के पार पहुंचने के साथ ही हीटवेव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वही दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर के चलते शहर में जलापूर्ति की मांग भी बढ़ने लगी है, अगर यही हालात रहे तो इस पर प्रशासन को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में ही सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाते शुरू कर दिये हैं, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। तापमान 35 से 40 डिग्री के बढ़ने के साथ ही दौसा जिले में हीटवेव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। भीषण गर्मी व सूरज के तीखे तेवर के चलते दोपहर बाद शहर के मुख्य मार्गों पर अघोषित कर्फ्यू के हालात पैदा हो गये हैं। वहीं

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर और तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है।

सफाईकर्मियों की हड़ताल से करौली शहर में पसरी गंदगी

करौली, (निर्सं)। नगर परिषद के संवेदक सफाईकर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगने से शहर का वातावरण दूषित हो रहा है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन की ओर से अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से आमजन में नाराजगी है।

बताया जा रहा है कि संवेदक कर्मचारियों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण वे हड़ताल पर चले गए हैं। यह स्थिति पहली बार नहीं है, बल्कि मानदेय नहीं मिलने के कारण समय-समय पर संवेदक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। शहर में इन दिनों कैलादेवी मेले की तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है।

कोतवाली के पास कचरे के ढेर जमा होने से वहां आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे श्री मदनमोहनजी

बताया जा रहा है कि संवेदक कर्मचारियों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिला है

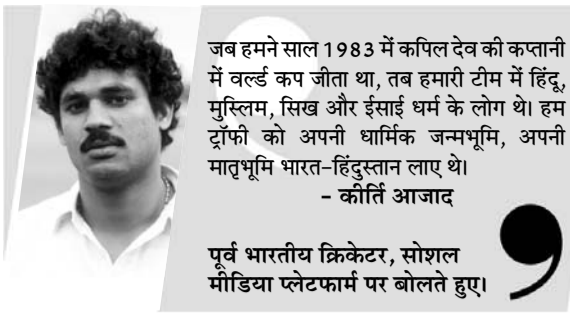
को लें जाने में सक्षम है। यात्री इस सेवा का लाभ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित हेड टीसी ऑफिस या सहायता बृथ पर संपर्क करके ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जबकि पांच वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए 30 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। फिलहाल एक बैटरी संचालित कार का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

इसी प्रकार हिंडीन दरवाजा मार्ग पर गंदी नालियों का पानी दिनभर सड़क पर बहता रहता है, जिससे राहगीरों को काफी कठिनाई होती है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर परिषद और जिला प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सूत्रों के अनुसार सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण नगर परिषद प्रशासन और कुछ पार्षद प्रतिनिधि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों से सफाई कर्तव्य का दबाव बना रहे हैं, जिससे अग्निशमन कर्मियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है।

को लें जाने में सक्षम है। यात्री इस सेवा का लाभ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित हेड टीसी ऑफिस या सहायता बृथ पर संपर्क करके ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जबकि पांच वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए 30 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। फिलहाल एक बैटरी संचालित कार का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

को लें जाने में सक्षम है। यात्री इस सेवा का लाभ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित हेड टीसी ऑफिस या सहायता बृथ पर संपर्क करके ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जबकि पांच वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए 30 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। फिलहाल एक बैटरी संचालित कार का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

को लें जाने में सक्षम है। यात्री इस सेवा का लाभ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित हेड टीसी ऑफिस या सहायता बृथ पर संपर्क करके ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जबकि पांच वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए 30 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। फिलहाल एक बैटरी संचालित कार



जब हमने साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, तब हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग थे। हम टॉफी को अपनी धार्मिक जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि भारत-हिंदुस्तान लाए थे।
- कर्तिक आजाद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए।



आज का खिलाड़ी



संजू सैमसन ने धमाकेदार पारी और टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। संजू ने तीन अहम मुकामों में भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। संजू को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं टीम इंडिया के तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने

संजू सैमसन

राष्ट्र टु जालोर, 11 मार्च, 2026

5

क्या आप जानते हैं? ... ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भिड़ेंगे। दोनों टीमों में 113 साल पहले भी लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच में भिड़ चुकी है।

बीसीसीआई 131 करोड़ भारतीय खिलाड़ियों को देगा, प्लेयर के खाते मोटी रकम से भर जाएंगे

नई दिल्ली, 10 मार्च। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए की ईनामी राशि का एलान किया है। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर बीसीसीआई ने टीम को 125 करोड़ रुपए देने का एलान किया था और इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। बीसीसीआई द्वारा एलान की गई राशि को खिलाड़ी, कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों में बांटी जाएगी। 131 करोड़ की राशि में से किसके कितने रुपए

मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी सामने आई है। बता दें कि भारत ने रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल मुकामों में 96 रनों से हराया और टी20 विश्व कप तीसरी बार अपने नाम किया। अब बीसीसीआई के द्वारा एलान की गई राशि को कैसे बांटा जाएगा ये कंफर्म हो गया है। बीसीसीआई ने इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी है कि राशि का

बंटवारा कैसे किया जाएगा। पीटीआई देवी और गोलकीपर पंथोई चोटिल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया पड़ा। सिडनी में खेले गए इस मुकामों में भारत ने लंबे समय तक गेंद पर नियंत्रण रखा और कई मौके भी बनाए, लेकिन अंतिम हिस्से में टीम गोल करने में नाकाम रही। इसी वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी और टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। भारत इससे पहले गुप स्ट्रेज में

डॉलर मिलेंगे। भारतीय रुपयों में इसकी कीमत लगभग 21.5 करोड़ रुपए है। भारतीय टीम को जीत के बाद बधाई देते हुए बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों और सेलेक्टर्स को बधाई देता है। हम भविष्य में उनकी निरंतर सफलता का कामना करते हैं।' बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, मैं टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देता हूँ। हम यही चाहते हैं कि वे आगे भी चाहते हैं कि वे सफल हों।'

जसप्रीत बुमराह ट्वेंटी-20 कम, वनडे ज्यादा खेलेंगे

2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पर रहेगा फोकस, वर्कलोड मैनेज करेगा बोर्ड

मुंबई, 10 मार्च। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब टी-20 सीरीज कम खेलेंगे। वे 2027 वर्ल्ड कप तक ज्यादा वनडे मैच खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए यह रणनीति बना रहे हैं। ताकि 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनकी तैयारी बेहतर हो सके। न्यूज एजेंसी ने के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अगले कुछ समय में द्विपक्षीय टी20 सीरीज में बुमराह को कम मौके दिए जा सकते हैं। बुमराह ने 19 नवंबर 2023 के बाद वनडे नहीं खेला। बुमराह ने 19 नवंबर

2023 के बाद कोई वनडे मैच नहीं खेला है। पिछली बार वे वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे क्रिकेट खेलने उतरे थे। अक्टूबर-नवंबर 2027 तक टी20 इंटरनेशनल टीम के लिए कम प्रारंभिकता वाला फॉर्मेट माना जा रहा है। इसी दौरान जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर सकते हैं। अब का अगला टूर्नामेंट 2027 का वनडे वर्ल्डकप होगा। उसी साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का

फाइनल भी खेला जाएगा। 2028 में अगला टी-20 वर्ल्ड कप, ओलिंपिक गेम्स और चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल है। सिलेक्शन कमेटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टीम मैनेजमेंट मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। बुमराह मुंबई इंडियंस के पेश अटैक की अगुआई करने वाले हैं। 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से बुमराह ने 42 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें 21 टेस्ट और 21 टी20 इंटरनेशनल शामिल हैं।



नन्हें खा क्रिकेट लीग भदौरिया की जीत में राहुल व भवित के नाबाद शतक

जयपुर, 10 मार्च। चंबल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित नन्हें खा मेमोरियल क्रिकेट लीग में टॉप जीतकर राजस्थान यूथ ने बल्लेबाजी करते हुए जयंत तान्वी 35, वरुण 34, रियान अली 39, नितिन सिंघल 24, कैफ गुड्डेज 41, गौरव पुनिया 17 रनों के सहयोग से 37 ओवर में 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गईं। भदौरिया एकेडमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए राहुल गर्ग 3, राजीव दुखतावा 2, देवांश सिंह ने 1-1 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भदौरिया एकेडमी ने सलामी बल्लेबाज राहुल गर्ग 109, भवित कुमावत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक लगाए और 10 विकेट से टीम को जीत दिलाई। आर. सी. ए. की सीनियर टूर्नामेंट होने के कारण मैच नहीं हो पाए थे, अब मैच चल रहे हैं।

भारत विमेंस फुटबॉल एशियन कप से बाहर

चाइनीज ताइपे ने 3-1 से हराया, कप्तान स्वीटी देवी और गोलकीपर पंथोई चोटिल, अस्पताल में भर्ती कराया गया

सिडनी, 10 मार्च। भारत विमेंस फुटबॉल एशियन कप से बाहर हो गया है। मंगलवार को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के आखिरी ग्रुप मैच में भारत को चाइनीज ताइपे के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही टीम का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। इस मैच में जीत भारत के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम दो गोल के अंतर से जीत दर्ज करनी

थी। मुकामों के दौरान भारतीय कप्तान स्वीटी देवी और गोलकीपर पंथोई चोटिल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया पड़ा। सिडनी में खेले गए इस मुकामों में भारत ने लंबे समय तक गेंद पर नियंत्रण रखा और कई मौके भी बनाए, लेकिन अंतिम हिस्से में टीम गोल करने में नाकाम रही। इसी वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी और टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। भारत इससे पहले गुप स्ट्रेज में

विगतनगर और जापान से भी हार चुका था। 12वें मिनट में चाइनीज ताइपे की बहदूत - मैच के 12वें मिनट में चाइनीज ताइपे ने बहदूत बना ली। संजू के खराब बैक पास के बाद जे डब्ल्यू चैन ने गेंद वाई एच सू को पास की, जिन्होंने खाली गोलपोस्ट में गेंद डाल दी। भारत ने 39वें मिनट में वापसी की। मनीषा कल्याण ने करीब 30 गज दूर से जोरदार शॉट लगाकर गोल किया और स्कोर 1-1 कर दिया।

पेनल्टी से फिर आगे निकला चाइनीज ताइपे - पहले हाफ के अतिरिक्त समय में चाइनीज ताइपे को पेनल्टी मिली। वाई वाई सू का शॉट पोस्ट से टकराया और गोलकीपर पंथोई से लागकर गेंद गोल में चली गई। इससे ताइपे ने 2-1 की बहदूत बना ली। दूसरे हाफ में भारत ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन 77वें मिनट में यू चिन चैन ने तीसरा गोल कर मैच लगभग तय कर दिया।

टी-20 वर्ल्डकप फाइनल में अर्शदीप पर जुर्माना

न्यूजीलैंड के मिचेल की ओर गेंद फेंकी थी, मैच फीस का 15 प्रतिशत कटा, डिमेंटि पाइंट भी मिला

नई दिल्ली, 10 मार्च। टी-20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल की ओर गेंद फेंकने की घटना के बाद ने उन पर कार्रवाई की। मंगलवार को जारी बयान में अर्शदीप की मैच फीस का 15 काटने के साथ उनके खाते में एक डिमेंटि पाइंट भी जोड़ दिया गया। 8 फरवरी को फाइनल में अर्शदीप ने गुस्से में आकर मिचेल की तरफ गेंद फेंकी थी। जो उनके पैड्स पर लगी थी। यह कार्रवाई की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन के मामले में की गई। फाइनल मैच रविवार को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था। इसमें भारत ने 96 रन से कीवी टीम को हराकर लगातार दूसरी और ओवरऑल तीसरा टी-20 वर्ल्डकप जीतने वाली पहली टीम बनी थी।

मिचेल की कोहनी पर बॉल लगी

न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में अर्शदीप ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद फेंक दी और वापस फेंकी, जो बल्लेबाज डेरिल मिचेल को लग गई। इसे आचार संहिता के आर्टिकल की 2.9 का उल्लंघन माना गया। इस नियम में मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की ओर अतृप्त या खतरनाक तरीके से गेंद या अन्य उपकरण फेंकने को गलत माना जाता है।

एक डिमेंटि पाइंट भी मिला

जुर्माने के साथ अर्शदीप के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेंटि पाइंट भी जोड़ा गया है। पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला मामला है। मैदान पर मौजूद अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और प्लेक्स स्टाफ, थर्ड अंपायर अलाउडान पलेकर और फोथ्र अंपायर फंडियन होल्डस्टॉक ने यह आरोप लगाया था। मैच

पांच ईरानी फुटबॉल खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने शरण दी

राष्ट्रीय गान विवाद के बाद लौटने से इंकार किया, एशियन कप खेलने गई थी खिलाड़ी

नई दिल्ली, 10 मार्च। एशियन कप से बाहर होने के बाद ईरान की महिला फुटबॉल टीम की पांच खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीजा देकर अपने देश में रहने की इजाजत दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क ने बताया कि इन खिलाड़ियों को पुलिस ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। दरअसल, पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच से पहले ईरान की टीम ने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया था। इसके बाद ईरान में कुछ लोगों ने टीम की आलोचना की और उन्हें सख्त सजा देने की मांग भी की। इसी वजह से खिलाड़ियों ने शरण मांगी थी। टीम में कुल 26 खिलाड़ी और स्टाफ मौजूद थे,

लेकिन फिलहाल सिर्फ पांच खिलाड़ियों ने ही शरण मांगी थी। बाकी खिलाड़ी अभी अपने फैसले पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार ईरान में रहते हैं और उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई का डर है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी पुष्टि की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी पुष्टि की कि इन पांच खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दे दिया गया है। इस वीजा के तहत वे ऑस्ट्रेलिया में रह सकती हैं, काम कर सकती हैं और पढ़ाई भी कर सकती हैं। इसी मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका भी इन खिलाड़ियों को शरण देने के लिए तैयार है।

खिलाड़ियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया ऑस्ट्रेलिया में ईरानी टीम को लेकर व्यापक अटकलें लगाई गईं और खबरें भी खूब छपीं जब खिलाड़ियों ने अपने पहले मैच

से पहले ईरानी राष्ट्रगान नहीं गाया। मंगलवार को मुंबई ऑस्ट्रेलिया के संघीय पुलिस अधिकारियों ने गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के एक होटल से पांच महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया था।

मंत्रि टोनी बर्क ने जानकारी दी वहां उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क से हुई और उनके मानवीय वीजा की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जानकारी मंत्रि ने कुछ घंटों बाद ब्रिस्बेन में पत्रकारों को ही। बर्क ने कहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह निर्णय प्रत्येक महिला के लिए कितना कठिन रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से कल रात खुशी और राहत का माहौल था। उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय महिलाओं के मुस्कुराते और ताली बजाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।

मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के नए पेंटिंग कोच बने

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर 2026 सीजन के लिए टीम से जुड़े

भोपाल, 10 मार्च। 2026 से पहले गुजरात टाइटंस ने अपनी कोचिंग टीम में बदलाव किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन को टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया। हेडन दो बार के वनडे वर्ल्ड कप विजेता हैं और अपने जमाने के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। हेडन की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब टीम अपनी बैटिंग युनिट को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश कर रही है। विक्रम सोलंकी बोले - हेडन के आने से युवाओं को फायदा होगा फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी ने कहा कि हेडन का अनुभव टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा।

हेडन की नियुक्ति पर बात करते हुए सोलंकी ने कहा, मैथ्यू हेडन का हमारी टीम से जुड़ना एक अहम पड़ाव है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका जो अनुभव रहा है और युवाओं को निखारने की जो उनकी काबिलियत है, उससे हमारी टीम को अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले सीजन के लिए वह हमारी बैटिंग लाइनअप को मजबूत करेंगे। हेडन बोले- हम गुजरात टाइटंस में बैटिंग का नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे अपनी नई जिम्मेदारी पर मैथ्यू हेडन ने कहा, अच्छी बल्लेबाजी वह होती है जो सामने वाली टीम पर दबाव बनाए, लेकिन महान बल्लेबाजी वह है जो पूरे खेल पर अपना कब्जा कर ले। गुजरात टाइटंस में हम बल्लेबाजी का यही स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। हेडन को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और पावरप्ले में डोमिनेट करने के लिए जाना जाता है, जो टी-20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी जरूरत है।

श्री सीमेंट कप टूर्नामेंट का हुआ आगाज आरपीसी ने जयगढ़ को हराकर जीता टूर्नामेंट का पहला मैच



जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर मंगलवार को श्री सीमेंट कप (आउट ऑफ हेट) टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट की शुरुआत टीम आरपीसी और टीम जयगढ़ के बीच मैच के साथ हुई। इस मुकामों

में टीम आरपीसी 3.5-3 के स्कोर से टीम जयगढ़ को हराकर मैच की विजेता बनी। विजेता टीम आरपीसी से हिज हाइनेस महाराजा सवाई षबाना सिंह ने 3 गोल किए। टीम से नरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह और जोशाहा अली मर्चेंट

भी खेले। यहां टीम को आधे गोल का एडवांटेज भी प्राप्त हुआ। वहीं, टीम जयगढ़ से विक्रामादित्य सिंह बरकाना, प्रताप सिंह कानोता और एलन शॉन माइकल प्रत्येक ने 1-1 गोल किया। टीम से अश्विनी शर्मा भी खेले। टूर्नामेंट

का दूसरा मुकामला 12 मार्च, गुरुवार को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा। दूसरा मैच टीम जयपुर और नहरागढ़ के बीच होगा। इस कप का फाइनल 15 मार्च, रविवार को खेला जाएगा।

कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
क्रमांक-स्टोर/2025-26/0915995 दिनांक 07.03.2026

संशोधित ऑक्शन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय शास्त्री चौपट्टी की दुकान संख्या 01 से 09 किराये पर दिये जाने हेतु क्रमांक/स्टोर/2025-26/1742 दिनांक 04.02.2026 को सूचना जारी की गयी थी। दिनांक 27.02.2026 को बोर्ड मीटिंग होने के कारण उक्त ऑक्शन को संशोधित किया जा रहा है।

सौभाग्य श्याम शीतली विश्वविद्यालय शास्त्री पार्क भरतपुर व्यावसायिक दुकानें मध्य ओपन स्टोर अस्थायी रजिस्ट्रेशन/अमानत राशि/दस्तावेज, जमा करने की कार्यवाही 09.02.2026 से दिनांक 06.03.2026 तक प्रा.06.00 बजे तक निमाहित की, जिसका होली अकराश होने के कारण संशोधित कर दिनांक 13.03.2026 सां. 6.00 तक यथा जावे एवं किसी ऑनलाइन नौलामी दिनांक 16.03.2026 दोपहर 03.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय सभागार में आयोजित की जावेगी।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
1. WAU2526S80060312
राज.सं.बा.द/सी/25/2210 सचिव

कार्यालय नगर परिषद, तिजारा (खैरथल-तिजारा) राज.
Email ID - tijara.jaipur@gmail.com Ph. No. 01469-262032 (O).
क्रमांक- न.प.ति. / 2025-26 / 2788 दिनांक- 06.03.2026

ई-निविदा सूचना - 17/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार में उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर पालिका / परिषद / निगम / स्वयंसेवक शासन विभाग के निविदाताओं से आग्रह द्वारा सम्बन्धित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त ई-निविदा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा देना आवश्यक है। निविदा देना अनिवार्य है। निविदा देना के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर <https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <https://eproc.rajasthan.gov.in> की वेबसाइट पर देखी एवं download कर प्राची की जा सकती है।
स्टेट पब्लिक प्रोक्विमेंट का NIB Code DLB2526B2524 है। आयुक्त
राज.सं.बा.द/सी/25/22097 नगर परिषद तिजारा

कार्यालय नगरपालिका सादड़ी (पाली) राजस्थान
क्रमांक : न.पा.सा. / 2026 / 5441-5443 दिनांक 06.03.2026

:-:कोरिजेन्डम ई-निविदा सूचना :-:
एवंद द्वारा समस्त पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सादड़ी द्वारा जारी ई-निविदा सूचना क्रमांक / न.पा.सा. / 2025-26 / 5151-5153 दिनांक 10.02.2026 को आमंत्रित की गई थी। उक्त ई-निविदा में किसी भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिये जाने से ई-निविदा में निम्नानुसार विवरण बढाई जाती है। शर्तें यथावत रहेंगी। सूचित रहे।

ऑनलाईन ई-निविदा करने हेतु अंतिम दिनांक व समय 16.03.2026 रात 06.00 बजे तक
मूल दस्तावेज, की.टी. जमा कराने की अंतिम तिथि 17.03.2026 रात दोपहर 1.00 बजे तक
ई-निविदा खोलने की दिनांक व समय 18.03.2026 रात दोपहर 4.00 बजे तक
राज.सं.बा.द/सी/25/22060 अधिसापी अधिकारी, नगरपालिका सादड़ी

DIRECTOR WORKS (EO)
Rajasthan Veterinary & Animal Science, Bikaner
क्रमांक : F (J)/DW(EO)/RAJUVA/2025-26/1038-1044 दिनांक - 07/03/2026

निविदा सूचना संख्या 12 वर्ष 2025-2026
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की ओर से विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त श्रेणी में, इस विश्वविद्यालय में एवं विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों, जो कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के सावक हो, पंजीकृत संवेदकों से ई-टेंडरिंग के माध्यम से निमाहित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदा प्राप्त की जावेगी। निविदा से सम्बंधित विवरण वेब साइट www.dip.rajasthan.gov.in/tenders.asp, www.rajuvas.org, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। UBN No. :VAU2526SLOB00138
राज.सं.बा.द/सी/25/22112 श.सहाय अधिकारी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर
(नगर निगम भवन, पोलीटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com) Tel: 0291-2651464
क्रमांक- 1286 दिनांक- 06.03.2026

ई-निविदा सूचना
UBN NO. DLB2526WSOB37121
नगर निगम जोधपुर के जॉन नं. 1, 5 एवं 8 एवं अन्य क्षेत्रों में सेवारत एवं अनुसंधान कार्य हेतु निविदाएं अनुमोदी एवं योग्य प्रतिभागियों से ई-निविदा प्रक्रिया से आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in <https://sg.rajasthan.gov.in/njodhpur> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। आयुक्त
राज.सं.बा.द/सी/25/22152 नगर निगम, जोधपुर

कार्यालय नगरपालिका उनियारा (टोक) राज.
क्रमांक / न.पा.उ. / स्टोर / 2025-26 / 4410 दिनांक : 06.03.2026

निविदा सूचना
नगरपालिका उनियारा (टोक) द्वारा नगर निकाय उनियारा एवं स्वयंसेवक शासन विभाग के समुचित वर्ग के सूचीबद्ध ठेकेदारों/संवेदकों एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में सक्षम श्रेणी के संवेदकों से निमाहित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं निविदा से सम्बन्धित विवरण व शर्तें वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। आयुक्त
NIB NO. DLB2526B2539 अधिसापी अधिकारी
राज.सं.बा.द/सी/25/22082 नगरपालिका उनियारा (टोक)

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुर्भाग सं 0294-2421255, 2420013, Helpline No. 0294-2426262 वेबसाइट - www.udajipurmc.org
क्रमांक : निविदा / 2025-26 / ई - 40 दिनांक - 06.03.2026

(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - हेतु 40/2025-26
नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु कुल राशि रु. 25.00 लाख के कुल 01 कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्विमेंट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के कार्य की प्रारम्भ तिथि 07.03.2026 एवं अंतिम तिथि 16.03.2026 तथा निविदा खुलने की तिथि 17.03.2026 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य सम्पन्न विवरण इंटरनेट साइट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
UBN No. UNP2526WSOB00167 अधिसापी अभियन्ता
राज.सं.बा.द/सी/25/22148 नगर निगम, उदयपुर

मंत्री 5 साल में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचें- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक दल की बैठक में सक्रिय विधायकों की सराहना की

जयपुर, 10 मार्च। मुख्यमंत्री ने 16 वीं विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक दल की बैठक ली। विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सदन में सक्रिय और प्रभावी प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को इसी तरह मजबूती से उठाते रहें।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों से राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विधायकों के कामकाज पर लगातार नज़र रखी जाती है और जनप्रतिनिधियों पर 'तीसरी आंख' भी रहती है, इसलिए सभी को अपने व्यवहार और कार्यशैली को लेकर सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने यह भी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को 16 वीं विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक दल की बैठक ली। विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे।

कहा कि विधायकों ने जो भी मांगें रखीं, सरकार ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी जनप्रतिनिधियों की बातों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि पांच साल के

कार्यकाल में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी है। मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और कम से कम आठ से दस घंटे क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने

कहा कि जनता से सीधा संवाद ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में आगामी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया।

ट्रंप ने पुतिन से लंबी वार्ता की

चर्चा है कि वार्ता ईरान जंग रूकवाने के बारे में थी

वाशिंगटन/माँस्को, 10 मार्च। अमेरिका-इज़राइल के ईरान के साथ जारी युद्ध और मध्य पूर्व में चरम पर पहुंचे तनाव को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू होने के शुरूआती संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सैन्य अभियान शुरू होने के बाद पहली बार सोमवार रात (ईडियन स्टैंडर्ड टाइम)रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलिफोन पर लंबी बातचीत की। दोनों ने करीब साठ मिनट तक चर्चा की। कहा जा रहा है कि वार्ता का अधिकांश हिस्सा ईरान पर केंद्रित रहा। ट्रंप ने अपने समकक्ष से यूक्रेन जंग पर भी कुछ समय तक चर्चा की।

द माँस्को टाइम्स, अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सप्रेस, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द टाइम्स (नेदरलैंड) की रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों नेताओं की वार्ता पर क्रेमलिन ने बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया कि सोमवार को यह वार्ता करीब एक घंटे तक चली।

पुतिन के हवाले से क्रेमलिन प्रवक्ता ने बयान में कहा कि ट्रंप ने अपने समकक्ष से ईरान युद्ध को जल्दी

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान वॉर रूकवाने के कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए हैं।

सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव रखे। पुतिन ने कहा वह खाड़ी नेताओं के साथ-साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन के संपर्क में हैं। क्रेमलिन ने कहा कि दोनों ने वेनेजुएला और ऊर्जा उद्योग के बारे में भी बात की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने पुतिन से ईरान और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर चर्चा की। एक्सप्रेस का आकलन है कि रूस ईरान का अहम साथी है। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि रूस इस युद्ध में ईरानियों की मदद कर रहा है। हालांकि ट्रंप ऐसा नहीं मानते पर वाइट हाउस के दूत स्टीवन विल्टकोफ ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि रूस को ईरान के साथ कोई भी खुफिया सूचना नहीं बांटनी चाहिए।

पुतिन की विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत बेहद साफ और आपसी हितों पर केंद्रित रही। उन्होंने

दवा किया कि पुतिन ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप को कई प्रस्ताव दिए। इस घटनाक्रम के बीच ईरान के उप विदेशमंत्री काजम गरीबाबादी के हवाले से एक अन्य रिपोर्ट में दवा किया गया है कि रूस ने युद्धविराम की शर्तों के लिए ईरान से संपर्क किया है। गरीबाबादी ने ईरान के सरकारी ब्राडकास्टिंग प्रेस टीवी पर कहा कि फ्रांस, चीन और रूस ने शांति प्रस्ताव की शर्तों पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है। गरीबाबादी की घोषणा के कई घंटे बाद ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, उनका "पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।"

ट्रंप ने कहा, "मैंने ईरान के लिए आप मेरी यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर मदद ली। साथ ही आप ईरान के साथ युद्ध बंद कराने में मददगार बनें।" पुतिन के करीबी उशाकोव ने यह भी कहा कि दोनों ने तेल बाजार में कीमतों में तेजी पर भी चर्चा की।

राज्यपाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आईसीयू 2 में भर्ती किया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवरस भी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक, राज्यपाल को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही किडनी में थोड़ी समस्या को देखते हुए यहां जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी की टीम की देखरेख में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं, राज्यपाल के यूरिन और ब्लड की दोबारा सैपिंग करारक उन्हें टैस्टिंग के लिए भिजवाया है। राज्यपाल के ट्रीटमेंट के लिए 7 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम का एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। इसमें जनरल मेडिसिन, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी तथा कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर हैं।

बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा

चंडीगढ़, 10 मार्च। बीएसएफ ने सीमा पार से हो रही तस्करी की कार्रवाई को असफल बनाते हुए, तरनतारन के खेमकरण सेक्टर में डेरोइन तस्करी का प्रयास कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को ढं कर दिया। इस संबंध में पाकिस्तान को सूचित किया गया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

'गैस के दाम बढ़ा दिए पर आपूर्ति नहीं हो रही है'

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 10 मार्च। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि वह गैस संकट को लेकर कुछ तथ्य छिपा रही है।

उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ना ही है, इसलिए सरकार को इससे निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करनी

■ **कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा, गैस सप्लाई में कमी के लिए सरकार ने पूर्व तैयारी क्यों नहीं की।**

चाहिए थी। राज्यपाल के नेता ने कहा कि सरकार ने गैस की कीमतों में वृद्धि तो कर दी, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, जिसका सीधा असर आम लोगों के साथ-साथ, होटलों और रेस्तरां पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अगर आने वाले वर्षों में वैश्विक स्थिति ऐसी ही रहती है, तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उन्होंने सरकार से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टोस कदम उठाने की मांग की। संसद में सरकार के बयान पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि शांति के लिए टोस कूटनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और सरकार की पहली प्राथमिकता उनके संरक्षण के लिए होनी चाहिए।

प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली

बम निरोधक दस्तों व डॉग स्कवॉड के साथ पुलिस ने सघन चैकिंग की

जयपुर, 10 मार्च। राजधानी जयपुर में मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। भारत सरकार का पासपोर्ट सेवा केन्द्र (ऑर्बिट मॉल) और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर (झाला) को ई-मेल के जरिए गैस बम से विस्फोट करने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया था।

सूचना मिलते ही, राजस्थान पुलिस, एटीएस और बम डिफ्यूज टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों कार्यालयों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालयों में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकाल दिया गया तथा एंटी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई।

जानकारी के अनुसार, धमकी भरा ईमेल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मिला, जिसमें दोपहर 1:10 बजे

■ **एहतियत के तौर पर सभी पासपोर्ट कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।**

ब्लास्ट होने की बात लिखी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की। करीब एक घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसे फर्जी ई-मेल मानकर जांच कर रही हैं, लेकिन एहतियत के तौर पर सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और ईमेल भेजने वाले स्रोत का पता लगाने

के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।

इसी तरह, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सर्वाईमाधोपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़, अलवर, दौसा, भरतपुर जिलों में भी पासपोर्ट कार्यालयों को धमकी का ई-मेल मिला। सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्तों, सिविल डिफेंस, डॉग स्कवॉड को बुलाया गया। हालांकि सर्च में कहीं भी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना नहीं है।

विपक्ष ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले तथा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी सत्र के दौरान सवाल उठा सकते हैं। इन घटनाओं के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की नीति पर सवाल उठा सकता है। तुणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा सदन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुरीक्षण का मुद्दा उठाया जाने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से जुड़े कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला उठा सकता है। इस बीच सरकार बजट सत्र के शेष हिस्से के दौरान बिजली संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। तथा सत्र के पूर्वाह्न के कई लंबित विधायी कार्यों को भी ले सकती है। कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा में चर्चा के लिए अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव ही सूचीबद्ध है।

घुसपैठ करते पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया

राजौरी, 10 मार्च। सेना के जवानों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश करते एक आतंकवादी को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया।

व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने दोपहर करीब तीन बजे एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर के झंगड़ के सामान्य इलाके में दो आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाया।

गोलीबारी होने पर एक पाकिस्तानी

■ **अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करते समय सुरक्षाबलों ने उन्हें निशाना बनाया।**

आतंकवादी को मार गिराया गया, जिससे नियंत्रण रेखा के किसी भी उल्लंघन को प्रभावी ढंग से रोका जा सका। दूसरे आतंकवादी का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह इलाके में छिपा हुआ है।

'राहुल निडर हैं, बेझिझक सच बोलते हैं'

प्रियंका गांधी ने संसद में यह भी कहा कि राहुल गांधी ही एक मात्र नेता हैं जिन्होंने 12 साल में एक बार भी सरकार के सामने सिर नहीं झुकाया

■ **प्रियंका ने यह टिप्पणियां तब की जब संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा राहुल की जगह प्रियंका बेहतर नेता प्रतिपक्ष होतीं।**

नैरु का कथन उद्धृत किया। इस पर प्रियंका ने राहुल को निडर नेता बताया। रिजिजू ने अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता क्यों

■ **प्रियंका ने यह टिप्पणियां तब की जब संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा राहुल की जगह प्रियंका बेहतर नेता प्रतिपक्ष होतीं।**

नैरु का कथन उद्धृत किया। इस पर प्रियंका ने राहुल को निडर नेता बताया। रिजिजू ने अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता क्यों

खड़ी हो गई। प्रियंका ने कहा, "मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज उन्होंने पंडित नेहरू का कथन अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, जिनकी वे दिन-रात आलोचना करते हैं। आज रिजिजू ने पंडित नेहरू के उस कथन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी।"

पदीय कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) परिसर में घुसे और दीवार और गेट को तोड़ दिया। यह कार्रवाई तत्कालीन अधिकारी के निर्देश पर हुई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में एफआर पेश कर दी। इसके खिलाफ दायर प्रोटेस्ट पिटिसन पर अदालत ने 10 फरवरी, 2010 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया। इसके खिलाफ दायर रिवीजन पर भी कोर्ट ने यह आदेश बहाल रखा। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई थी और जेडीए प्रबंधन अधिकारी होने के कारण उन्हें इसका अधिकार था। ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

'होर्मुज़ स्ट्रेट रोका तो ईरान पर कहर बरसेगा'

अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट रोकने के लिए ईरान को कड़ी चेतावनी दी

वाशिंगटन, 10 मार्च। अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल आपूर्ति बाधित करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान इस अहम समुद्री मार्ग से तेल के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, तो अमेरिका उसे कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा।

हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज़

■ **ज्ञातव्य है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है और यह मार्ग समुद्र में जहाजों के परिहान के लिए बहुत जरूरी है।**

स्ट्रेट में तेल आपूर्ति रोकने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में ईरान पर मौत, आग और कहर

बरसेगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी सैन्य अभियान "ऑपरेशन एफिक फ्यूरी" को लेकर नई जानकारी साझा की गई। इस दौरान जॉर्डन चीफ्स ऑफ स्टॉफ के चेयरमैन डैन केन ने बताया कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा और संभावित सैन्य विकल्पों का आकलन कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब तक ईरान के मिसाइल, नौसैनिक और सैन्य ढांचे से जुड़े 5,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं।

'हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं'

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने अमेरिका की कहर बरसाने की धमकी पर जवाब दिया

तेहरान/वाशिंगटन, 10 मार्च। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के 11 वें दिन तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमले किए जा सकते हैं। इसके जवाब में ईरान के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि देश किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा कि कोई भी ताकत ईरान को मिटा

■ **उन्होंने ईरान 6 हजार साल पुरानी सभ्यता है कई हमलावरों ने इसे खत्म करने की कोशिश की पर वे सफल नहीं हो सके।**

नहीं सकती। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान कम से कम छह हजार साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके मुताबिक जो लोग ईरान को खत्म करने का सपना

देखते हैं, वे इतिहास को नहीं समझते। वहीं, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी जनता किसी भी धमकी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि पहले भी कई शक्तिशाली ताकतों ने

ईरान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रही। लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को अपेक्ष संदेश देते हुए कहा कि जो लोग ईरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए। उनके अनुसार इतिहास गवाह है कि ईरान पर हमला करने वाले कई आक्रमणकारी समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन ईरान कायम रहा।

अपने फायदे के लिए विभिन्न देशों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कोल्ड वॉर के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका सत्ता परिवर्तन अभियानों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वर्ष 1953 में, सीआईए ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसदेद की सरकार को उखाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। इस ऑपरेशन ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बहाल किया। शाह का शासन कुछ समय के लिए स्थिरता लाया और वाशिंगटन के साथ करीबी संबंध बनाए। तानाशाही शासन और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ आक्रोश ने अंततः 1979 में इस्लामिक क्रांति का रूप लिया, जिसने राजतंत्र को इस्लामिक गणराज्य से बदल दिया और ईरान को अमेरिका के प्रमुख विरोधियों में से एक बना दिया। वर्ष 1954 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्वाटेमाला में एक तख्तापलट को समर्थन दिया, जिसने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति जैकोबो आर्बेन्स को उखाड़ फेंका। वाशिंगटन उसके द्वारा किए गए भूमि सुधारों और लेफ्टिस्ट रूझानों को अमेरिका के लिये खतरा मानता था। इस

तख्तापलट ने सैन्य शासन की शुरूआत की और दशकों लंबे नागरिक संघर्ष और दमन को जन्म दिया, जिसके कारण ग्वाटेमाला राजनीतिक रूप से कई वर्षों तक अस्थिर रहा। वर्ष 1961 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा में फिडेल कास्त्रो की सरकार को उखाड़ने का प्रयास किया, जिसे असफल ने केवल विफल हो गया, बल्कि कास्त्रो की स्थिति मजबूत हुई, साथ ही क्यूबा सोवियत संघ के साथ और अधिक मजबूती से जुड़ गया, जिससे शीत युद्ध के तनावों में वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में भी सैन्य हस्तक्षेप किया, ताकि वह सिविल वॉर को रोक सके वाशिंगटन को लगता था कि यह वॉर वामपंथियों के नियंत्रण में जा रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने एक और अधिक रूढ़िवादी सरकार की स्थापना में मदद की। हालांकि इस हस्तक्षेप ने कुछ हद तक व्यवस्था बहाल की, तथा देश में तानाशाही राजनीतिक संरचनाओं को भी लंबा किया।

वर्ष 1973 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिली की सेना के तत्वों का समर्थन किया, जिन्होंने समाजवादी राष्ट्रपति सल्व्वादोर अलेंडे की सरकार को उखाड़ फेंका। इस तख्तापलट के बाद जनरल अगस्तो पिनोचेट को सत्ता में लाया गया। पिनोचेट के शासन के तहत चिली ने राजनीतिक स्थिरता और अधिक पुनर्गठन का अनुभव किया, लेकिन इसके साथ ही व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ। देश अंततः 1990 में लोकतंत्र में वापस लौट आया। वर्ष 1980 के दशक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दो और देशों में सौधे सैन्य हस्तक्षेप किए। वर्ष 1983 में, अमेरिकी बलों ने ग्रेनेडा पर आक्रमण किया, जहां एक मार्क्सवादी सरकार के भीतर आंतरिक उथल-पुथल के बाद हुए इस हस्तक्षेप से शासक जुंटा को हटा दिया गया और चुनावों और अपेक्षाकृत स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1989 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा पर आक्रमण किया, ताकि सैन्य शासक मैनुएल नोरेगा को हटाया जा सके, जो अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोपों में अभियुक्त था।

नोरेगा को गिरफ्तार किया गया और पनामा ने बाद में एक स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया। कोल्ड वॉर के बाद के युग में, शासन परिवर्तन युद्ध और भी विवादास्पद हो गए। 11 सितंबर के हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तालिबान शासन को उखाड़ फेंका, जो अल-कायदा को शरण दे रहा था। हालांकि काबुल में एक नई सरकार स्थापित की गई, लेकिन देश दो दशकों तक संघर्ष में डूबा रहा। वर्ष 2021 में अमेरिकी वापसी के बाद, तालिबान सत्ता में वापस आ गया, जिससे हस्तक्षेप की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर सवाल उठे। वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण का उद्देश्य सद्दाम हुसैन को हटाना और कथित रूप से विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना था। सद्दाम का शासन खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद कई सालों तक विद्रोह, संप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जिसमें चरमपंथी सत्ता का उभार हुआ। इराक ने अंततः एक निर्वाचित